ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -42 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 18 जून से 24 जून (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

पीएम मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान

नयी दिल्ली। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया की तीन दिन की यात्रा पर गए पीएम मोदी को राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सोमवार रात एक विशेष समारोह में स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, फर्स्ट क्लास' से सम्मानित किया।

प्रधानमंत्री ने इस विशिष्ट सम्मान के लिए राष्ट्रपति, स्लोवाकिया की सरकार और जनता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। सम्मान स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 1.4 अरब लोगों तथा भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी मैत्री संबंधों को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के लोगों को जोड़ने वाली आत्मीयता, विश्वास और स्नेह का प्रमाण बताते हुए आशा व्यक्त की कि यह सम्मान दोनों देशों की भावी पीढ़ियों को उनकी विशेष मित्रता को आगे भी सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाला 33वां अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक सम्मान है। मोदी जी 7 देशों के 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन शहर के लिए रवाना होंगे। भारत इस सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहा है।

आर्थिक और तकनीकी साझेदारी के प्रयास, फ्रांस में भारत का हासिल क्या?

दरअसल, जी7 के लिए भारत का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। यह ठोस आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारियों में परिलक्षित होता है। हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता इसका प्रमाण है। नीस में भारत इनोवेट्स जैसी पहल भी इसका उदाहरण है।

चीन के बढ़ते निर्यात पर होगी चर्चा इसका यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर असर का मुद्दा उठाएंगे मैक्रों

जी7 शिखर सम्मेलन 2026 में आज चीन के बढ़ते निर्यात और उसके यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस विषय पर सदस्य देशों के नेताओं के सामने अपनी चिंताएं रख सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में मैक्रों ने चेतावनी दी थी कि चीन से होने वाला निर्यात यूरोप के बड़े हिस्से के उद्योगों को लगभग खत्म कर रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि इस खतरे को समझने में यूरोप ने काफी देर कर दी। इस बीच, यूरोपीय सहयोगी देशों की कोशिश है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपीय संघ (श्व) और कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगियों पर दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाने की नीति से पीछे हटने के लिए राजी किया जाए। यूरोपीय देशों का मानना है कि अमेरिका को अपने सहयोगी देशों के साथ व्यापारिक टकराव बढ़ाने के बजाय चीन से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का संयुक्त रूप से मुकाबला करना चाहिए।

शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर स्वामी राजीव लोचन दास महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के महंत सुरेंद्र दास महाराज, शदाणी दरबार से उदय लाल तथा कबीर आश्रम सोनपैरी के देवकर साहब जी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर संत-महात्माओं ने छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं नैतिक शिक्षा से जुड़े पारंपरिक श्लोकों और मंत्रों को पुनः शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

संतों ने कहा कि पूर्व में विद्यालयों में विद्यार्थियों को च्गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरज्ञ जैसे मंत्रों एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराया जाता था, जिससे बच्चों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता था। समय के साथ ये परंपराएं शैक्षणिक वातावरण से धीरे-धीरे विलुप्त होती गईं, किंतु अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुनः स्थापित करने की पहल अत्यंत स्वागतयोग्य है। संत समाज ने कहा कि विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र तथा अन्य प्रेरणादायी वैदिक एवं सांस्कृतिक प्रार्थनाओं का समावेश बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों के विकास का आधार भी है। हमारी सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र एवं अन्य प्रेरणादायी प्रार्थनाओं के समावेश से विद्यार्थियों में अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा।

यह पहल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक संस्कारित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

संक्षिप्त समाचार

'म्यूल अकाउंट' उपलब्ध करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार

नयी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में 'म्यूल अकाउंट' (फर्जी बैंक खातों) उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर पूरे देश में सक्रिय साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विजय कुमार (31), प्रदीप कुमार (42), यतेंद्र कुमार (23), मुकेश (24), विनेश (37), गुरबाज सिंह (27), अमन (27), सूरज यादव (24), गौरव नाहर (22) और लक्ष्मण (33) है।

बढ़त के साथ खुले शेयर बाजार

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गयी। बीएसई का सेंसेक्स 262.44 अंक की बढ़त में 76,526.77 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 297.44 अंक (0.39 प्रतिशत) ऊपर 76,561.77 अंक पर था। बाजार में चौतरफा लिवाली है। धातु समूह को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक इस समय ऊपर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 70 अंक की मजबूती के साथ 23,923.90 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 76.20 अंक यानी 0.32 प्रतिशत चढ़कर 23,930.10 अंक पर रहा।

डीजल, विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा

नयी दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है।

डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है। इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी।

साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

अमेरिकी बी-52 बॉम्बर विमान उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त, आठ लोगों की मौत

वॉशिंगटन। कैलिफ़ोर्निया के एडवर्ड्स हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी वायु सेना का बी-52 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

बेस ने यह भी पुष्टि किया कि बी-52 बॉम्बर के चालक दल के आठ सदस्यों के मारे जाने की आशंका है। यह जानकारी एडवर्ड्स वायु सेना बेस ने दी।

बेस ने एक बयान में कहा, आठ लोगों को लेकर जा रहा वायु सेना का बी-52 स्ट्रैटोफ़ोर्ट्रेस विमान, एक रूटीन मिशन के दौरान आज सुबह 11ः20 बजे पीडीटी (भारतीय समयानुसार सोमवार रात 11ः50 बजे) उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि इस हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम मौके पर मौजूद है और अधिकारी सभी लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेस ने बताया कि हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया और आने वाले सभी विमानों का रास्ता बदला जा रहा था।

बयान में कहा गया, अगले आदेश तक सभी गैर-व्यावसायिक विज़िटर पास निरस्त कर दिए गए हैं, ताकि संस्थान पूरी तरह से आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। अमेरिकी मीडिया ने दुर्घटना के वीडियो जारी किए हैं, जिनमें ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जला हुआ दिख रहा है, विमान का मलबा मुश्किल से ही नज़र आ रहा है और कुछ जगहों पर धुआं उठ रहा है।

एक जुलाई से बिजली महंगी, घरेलू उपभोक्ताओं पर 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई विद्युत दरों की घोषणा कर दी है।

आयोग द्वारा अनुमोदित नयी दरें आगामी एक जुलाई से पूरे प्रदेश में प्रभावी होंगी। संशोधित टैरिफ के तहत घरेलू, वाणिज्यिक तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 30 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की गई है। वहीं वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक दरें बढ़ाई गई हैं। कृषि पंपों की बिजली दरों में भी 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि स्वीकृत की गई है। आयोग ने गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को राहत देते हुए ऊर्जा प्रभार पर मिलने वाली छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी है।

अमेरिका के साथ समझौते के बावजूद ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार: पेज़ेशकियान

तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान-अमेरिका समझौता युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है लेकिन ईरान किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। पेज़ेशकियन ने एक्स पर कहा, जिस बात पर सहमति बनी है वह युद्ध रोकने और बातचीत शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन अभी अंतिम समझौता होना बाकी है। ईरान का इस्लामिक गणराज्य सभी विकल्पों के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि ईरान की सरकार अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के बिना भी या उसके साथ लोगों की सेवा करेगी। पेज़ेशकियन ने बताया कि अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन तैयार करने में ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अहम भूमिका निभाई।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली धाराओं को शामिल करने में सम्मानित सर्वोच्च नेता के मार्गदर्शन की सबसे बड़ी भूमिका रही है और हम इसके लिए उनके आभारी हैं। 15 जून को, ईरान और अमेरिका ने उस ज्ञापन के पूरा होने की पुष्टि की, जिस पर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में हस्ताक्षर होने हैं। ईरानी पक्ष ने बताया कि इस ज्ञापन में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई खत्म करने की बात कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पुष्टि किया कि ईरान के साथ ज्ञापन पर वास्तव में हस्ताक्षर हो चुके हैं।

ईरान ने कहा कि ज्ञापन के बाद, दोनों पक्ष एक अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे, जिससे ईरान के परमाणु मुद्दे और तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का समाधान हो सकेगा।

यस बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, दिल्ली-मुंबई समेत 17 ठिकानों पर छापा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक घोटाले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, मुंबई और खंडाला सहित 17 स्थानों पर एक साथ छापा मारा है। अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों के अलावा इनके प्रमोटरों, निदेशकों, कर्मचारियों तथा यस बैंक के एक पूर्व कर्मचारी के ठिकानों पर की गई।

ईडी की जांच वित्त वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान मैकस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों के यस बैंक के ऋणों के कथित फर्जी हस्तांतरण से जुड़ी है। अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान का उद्देश्य उन सबूतों को जुटाना है जो मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े हैं। जांच एजेंसी को शक है कि कुछ

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच मिलीभगत कर सर्कुलर लेनदेन किए गए, जिनके जरिए संकटग्रस्त परिसंपत्तियों पर कथित रूप से अनुचित तरीके से नियंत्रण हासिल किया गया। ईडी यह भी जांच कर रही है कि नीलामी के दौरान परिसंपत्तियों का जानबूझकर कम मूल्यांकन किया गया या नहीं, साथ ही बढ़ा-चढ़ाकर और कथित रूप से फर्जी दावों के जरिए लाभ पाने की कोशिश की गई या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन के साक्ष्यों की जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कोई भी उपभोक्ता 22 जून तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा

सरकार ने नीट पुनर्परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम एप पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध

नयी दिल्ली। सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी पाबंदी लगा दी है। यह कदम राट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) ने उठाया है।

सरकार के इस निर्णय के बाद कोई भी उपभोक्ता 22 जून तक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी मैसेज को एडिट भी नहीं कर पाएंगे।

एनटीए ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले गिरोह कथित तौर पर नीट उम्मीदवारों को ठगने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और पेपर लीक होने के झूठे दावे करते थे।

एनटीए के अनुसार भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एनटीए और राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स को बंद करवाने में मदद की है। एनटीए ने बताया है कि एक-एक करके चैनलों पर कार्रवाई करने से भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होने पर प्लेटफ़ॉर्म-स्तर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। एनटीए के मुताबिक 'पेपर लीक और री-एग्जाम 2026' जैसे नामों वाले चैनलों ने कथित तौर पर नकली पेपर के लिए उम्मीदवारों से हज़ारों से लेकर लाखों रुपये की मांग की। एनटीए ने दावा किया है कि टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर की वजह से एडमिन पुरानी फाइलों को बदलकर उनकी जगह नयी फाइलें डाल सकते थे, जबकि ओरिजिनल टाइमस्टैम्प वही रहता था। इस वजह से परीक्षा के बाद गुमराह करने वाले सबूत बन जाते थे। एनटीए ने कहा है कि इस निर्णय से असली उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे लेकिन यह सिर्फ परीक्षा की अवधि तक ही लागू रहेगी और इसका मकसद परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना है। एनटीए ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि 21 जून 2026 को होने वाली पुनर्परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी।

अल-नीनो से निपटने की रणनीति, हर हफ्ते होगी बैठक : शिवराज सिंह चौहान

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में अल-नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है, वहां के चिह्नित जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि विभाग, केवीके और अन्य विस्तार तंत्र के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जायें। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में जिला स्तर पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाये, ताकि हर किसान को यह पता रहे कि उसके क्षेत्र के लिए कौन-सी सावधानियां और कौन-से फसल विकल्प अधिक सुरक्षित हैं। वह यहां उच्च स्तरीय साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशभर की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही, संभावित अल-नीनो परिस्थितियों पर गहन चर्चा की। उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दलहन में आत्मनिर्भरता और कम बारिश वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजना पर विशेष जोर देते हुए साफ संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में अल-नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए चौहान ने साफ निर्देश दिया कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान कर राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसलवार आकस्मिक योजना तैयार किये जायें।

जलभराव और आवागमन की समस्या होगी दूर, पटरीपार के चार वार्डों में शुरू होंगे निर्माण कार्य, विकास की रफ्तार तेज, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का शुभारंभ

75 लाख रुपये से अधिक के नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के पटरीपार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महापौर अलका बाघमार ने लोककर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 एवं 44 में 75 लाख रुपये से अधिक की लागत से होने वाले नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। भूमिपूजन कायक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से जल निकासी और आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने विकास कार्यों की स्वीकृति एवं भूमिपूजन पर महापौर एवं निगम प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

चार वार्डों में होंगे विकास कार्य, जल निकासी समस्या से मिलेगी राहत- भूमिपूजन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास वार्ड में हिरामन साहू के घर से रानू के घर तक तथा पवन के घर से परऊ यादव के घर के पास तक लगभग 19 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 सिकोला भाठा की विभिन्न गलियों में 18 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य होगा। वार्ड क्रमांक 15 सिकोला बस्ती में मानिकपुरी के घर तक तथा निर्मला के घर से प्रकाश के घर तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य लगभग 18 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। वहीं वार्ड क्रमांक 16 सिकोला बस्ती कर्मचारी नगर में साहू भवन से मुख्य नाला तक 20 लाख रुपये की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य संपादित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर होगी, बारिश के दौरान जल निकासी बेहतर होगी तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।विकास कार्यों से बदलेगी पटरीपार क्षेत्र की तस्वीर : महापौर अलका बाघमार-इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, नाली और पुलिया निर्माण के कार्य लगातार स्वीकृत किए जा रहे हैं। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव और आवागमन की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी तथा पटरीपार क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का स्तर और बेहतर होगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में पार्षद ललिता ठाकुर, युवराज कुंजाम, खिलावन मटियारा, रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, भाजपा जिला प्रवक्ता अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष मनमोहन सिंह, सहायक अभियंता संजय ठाकुर,उप अभियंता सिद्धार्थ साहू सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने विकास कार्यों के लिए नगर निगम एवं महापौर का आभार व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने की अपेक्षा जताई।

शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास की रफ्तार तेज-नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वर्तमान में विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली, पुलिया, पेयजल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य लगातार स्वीकृत और प्रारंभ किए जा रहे हैं। निगम का लक्ष्य शहर के प्रत्येक वार्ड में नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाकर समग्र विकास को गति देना है, ताकि आमजन को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

वार्ड 30 और 31 में विकास को मिली रफ्तार, 82 लाख से अधिक के निर्माण कार्य होंगे शुरू

महापौर एवं सभापति कराया 82 लाख के कार्यों का शुभारंभ

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के बाजार क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नागरिकों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 82 लाख रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद एवं सभापति श्याम शर्मा, लोककर्म विभाग प्रभारी देव नारायण चंद्राकर, सांस्कृतिक विभाग प्रभारी एवं वार्ड क्रमांक 31 की पार्षद हर्षिका संभव जैन सहित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की उपस्थिति में आरसीसी सड़क, नाली एवं पुलिया निर्माण कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। भूमिपूजन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 में तेजपाल के निवास से डिसेंट सैलून तक 25 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण तथा तमेरपारा के विभिन्न स्थानों पर 17 लाख रुपये की लागत से नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य किए जाएंगे। वहीं वार्ड क्रमांक 31 में सिंडिकेट बैंक से स्वाध्याय भवन एवं सिद्धार्थ नगर बस्ती तक 12 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, आपापूरा से आबकारी कार्यालय, रजा खोखर कार्यालय, गवलीपारा होते हुए वर्धमान स्थापक भवन तक 15 लाख रुपये की लागत से आरसीसी सड़क निर्माण तथा हनुमान नाला से गुप्ता कॉम्प्लेक्स तक 13 लाख रुपये की लागत से नाली निर्माण कार्य कराया जाएगा। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निगम का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर नागरिकों को बेहतर आवागमन एवं जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से जल निकासी एवं आवागमन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने विकास कार्यों की स्वीकृति और शुभारंभ पर महापौर के प्रति आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर एमआईसी सदस्य शेखर चंद्राकर, नीलेश अग्रवाल, संभव जैन, रजा खोखर सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महापौर निधि के कार्यों की हुई समीक्षा, अधिकारियों से मांगी प्रगति रिपोर्ट, फील्ड में रहकर कार्यों की निगरानी करें अधिकारी, निर्माण सामग्री की जांच के दिए निर्देश

विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा से कोई समझौता नहीं : महापौर अलका बाघमार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर अलका बाघमार की अध्यक्षता में महापौर कक्ष में शहर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत व महापौर निधि के किए जा रहे कार्यों, सड़क डामरीकरण, सीमेंट कांक्रीट सड़कों, नाली-पुलिया निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेवर ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था एवं शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। महापौर अलका बाघमार ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की तथा कार्यों को निर्धारित समयसीमा एवं मानक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने महापौर निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से जानकारी ली कि एक वर्ष में प्राप्त 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि से कितने कार्य पूर्ण हुए हैं तथा कितने कार्य प्रगतिरत अथवा शेष हैं। उन्होंने पुराने कार्यों के साथ-साथ नवीन स्वीकृत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं फील्ड में उपस्थित रहकर निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सकें। भूमिपूजन के उपरांत संबंधित स्थल पर शिलापट्ट स्थापित करने तथा कार्य की प्रगति का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड संधारित कर जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए गए। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियां समन्वय के साथ कार्य करें। लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

जनहित के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में निगम के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर,शेखर चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकर,कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, पंकज साहू, विनोद मांझी,अपर्णा मिश्रा सहित अधिकारी/ कर्मचारी मौजूद रहे।

उधारी रकम वसूलने घर घुसकर मारपीट

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में गुण्डा तत्वों एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने उधारी रकम की जबरन वसूली के लिए घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी एवं उसके दो साथियों मनीष परियानी और गिरीश माखीजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामले में आशीर्वाद पूरम कॉलोनी रायगढ़ निवासी कमलेश सिंह उम्र 52 वर्ष द्वारा 13 जून को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह कोयला ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता है। प्रार्थी ने बताया कि कुडेकेला निवासी ललेश अग्रवाल का लगभग 07 लाख रुपये भुगतान आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिछले करीब तीन वर्षों से नहीं कर पाया है। प्रार्थी के अनुसार, 11 जून की दोपहर गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी अपने हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर अपने साथी मनीष परियानी एवं गिरीश माखीजा के साथ उसके घर में जबरन घुस आया। आरोपियों ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि तू हम लोगों को नहीं जानता है, तेरा मर्डर करवा देंगे।ष् इसके बाद ललेश अग्रवाल का पैसा वापस करने की बात कहते हुए पीड़ित से 10 लाख रुपये की मांग की गई तथा हाथ-मुक्के और डंडे से उसकी मारपीट की गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गुण्डा बदमाश कपिल सोलंकी की गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के संज्ञान में आने पर उन्होंने कोतवाली पुलिस को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी गई। र्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी कपिल सोलंकी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई।

विचाराधीन बंदी की अस्पताल में मौत मामले ने पकड़ा तूल, परिजनों ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग, हिरासत में पुलिस व जेल में मारपीट का किया दावा

रायगढ़। जिला जेल रायगढ़ में न्यायिक हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधायक, कलेक्टर, एसपी और कोतरारोड़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और जेल अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज करने तथा परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। रायगढ़ जिला मुख्यालय रविवार की सुबह गांव के ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे यहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि ग्राम नावापारा निवासी 30 वर्षीय संजय बघेल को 10 जून को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा एक शराब संबंधी मामले में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने संजय बघेल के साथ मारपीट की और मामले को रफा-दफा करने के लिए कथित रूप से दो लाख रुपये की मांग की गई। आरोप है कि बाद में सौदेबाजी के तहत 40 हजार रुपये लेने के बावजूद उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। परिवार का दावा है कि संजय बघेल पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं थी। वह अपने माता-पिता, पत्नी और दो नाबालिग बेटियों का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल और पुलिस प्रशासन की हिरासत में उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिसके कारण उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और मुंह से खून निकल रहा था। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि संजय की मौत की सूचना परिजनों को समय पर नहीं दी गई। परिवार का आरोप है कि मौत के बाद पहले उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में सूचना दी गई, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है। परिजनों का कहना है कि जब उन्हें शव दिखाया गया तब शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए, जिनके फोटो और वीडियो उनके पास मौजूद हैं। मृतक के परिवार ने मांग की है कि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज की जांच, न्यायिक एवं स्वतंत्र एजेंसी से जांच तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

फर्जी दस्तावेजों से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के खेल की जांच तेज, ट्रेवल्स एजेंसी में पुलिस-आरटीओ की संयुक्त दबिश करीब 180 दस्तावेजों की हो रही तस्दीक

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम विदित हो कि बीते 17 अप्रैल को नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पुलिस, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर समय-समय पर संयुक्त जांच एवं कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देशों के पालन में संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नवसीखिया चालक हेवी वाहन चलाने के लिए जारी लाइसेंसों का उपयोग कर भारी वाहनों का संचालन कर रहे हैं तथा 11 जून को पुलिस को लिखित आवेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि स्थानीय स्तर पर संचालित बाबा ट्रेवल्स नामक संस्थाध्एजेंसी द्वारा कथित रूप से ओडिशा एवं अन्य राज्यों के निवासियों के लिए फर्जी एवं भ्रामक दस्तावेज तैयार कर उन्हें रायगढ़, छत्तीसगढ़ का निवासी दर्शाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर सत्यापन के लिए नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा एवं यातायात उप पुलिस अधीक्षक उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आरटीओ एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बाबा ट्रेवल्स में दबिश दी गई। जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों में कई आवेदकों के पते समान पाए गए। प्रारंभिक जांच मंस यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि बाहरी राज्यों के आवेदकों के लिए स्थानीय स्तर पर किरायानामा एवं शपथ-पत्र तैयार कर उन्हें रायगढ़ का निवासी दर्शाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कराया गया। जांच के दौरान यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के तहत निर्धारित परीक्षण में वास्तविक आवेदक के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को शामिल कर परीक्षण दिलाए जाने के बाद लाइसेंस जारी कराए गए हो सकते हैं। इस संबंध में जांच टीम द्वारा लगभग 180 लाइसेंसधारियों के दस्तावेजों की विस्तृत जांच एवं सत्यापन किया जा रहा है।

अवैध बोर खनन करते हुए सुमित्रा बोरवेल की मशीन जब्त

रायगढ़। भीषण गर्मी और लगातार गिरते भू-जल स्तर के बीच प्रशासन ने अवैध बोर खनन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। घरघोड़ा तहसील के ग्राम रायकेरा में अवैध रूप से बोर खनन की सूचना पर तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर छापेमारी की और सुमित्रा बोरवेल के वाहन को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। जिले में जल संकट को देखते हुए नए बोरवेल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों को दरकिनार कर भू-जल दोहन में लगे हुए हैं। ग्राम रायकेरा में भी प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन किए जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वर्तमान में क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है और भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे समय में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी तरह गंभीर है।

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार का नया बोरवेल नहीं खोदा जाएगा। इसके बावजूद सुमित्रा बोरवेल द्वारा किए जा रहे अवैध खनन प्रयास पर कार्रवाई कर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की मांग की है। तहसीलदार की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में भू-जल संरक्षण को लेकर प्रशासन की गंभीरता साफ नजर आई है।

अग्रसेन चौक से हटाए गए यातायात बाधित ठेले-खोमचे, निगम की सख्त कार्रवाई

अतिक्रमणकारियों को चेतावनी : दोबारा सड़क घेरने पर होगी सामान जब्ती व जुर्माना

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर अग्रसेन चौक एवं उसके आसपास सड़क एवं आवागमन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले-खोमचों को हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर के नेतृत्व में निगम अमले एवं पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। अभियान के दौरान सड़क किनारे एवं चौक क्षेत्र में यातायात बाधित कर रहे सभी ठेले-खोमचों को हटवाया गया, जिससे आवागमन सुचारू हो सके तथा नागरिकों को जाम एवं असुविधा से राहत मिल सके। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर ने संबंधित ठेला संचालकों एवं व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़क, चौक एवं आवागमन क्षेत्र में दोबारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था बाधित न करें। यदि भविष्य में पुनः अतिक्रमण करते पाए गए तो निगम द्वारा सामान जब्त करने के साथ-साथ नियमानुसार जुर्माना एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। निगम प्रशासन द्वारा प्रमुख चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं व्यस्त मार्गों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों एवं सड़क मार्गों पर अतिक्रमण न करें तथा शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और यातायात बाधा मुक्त बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

राज्य में भीषण गर्मी के हिटवेव में स्कूल चलें हम नन्हे विद्यार्थियों की सेहत से खिलवाड़ की आहट

राज्य सरकार के फरमान से पालकों में विरोधाभास

डोंगरगांव नगर। छग में भीषण गर्मी के मौसम में एक तरफ जहाँ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने 16 जून से स्कूल खोलने का फरमान जारी कर दिया है। भयंकर लू हीटवेव एवं झुलसा देने वाली उमस भरी गर्मी के मध्य नौनिहालों को स्कूल भेजने के निर्णय को लेकर सरकार के प्रति विरोधाभास पनपने लगी है। दरअसल हीटवेव के कारण सरकार खुद रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को दोपहर में घरों से न निकलने की सलाह दे रही है, तो फिर मासूम बच्चों को उसी भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है ? यह प्रशासन के कथनी और करनी के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। वहीं राजधानी में वातानुकूलित कमरों में बैठकर फैसले लेने वाले अफसरान को शायद इस बात का तनिक भी इल्म नहीं है कि 45 डिग्री के तापमान में स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ेगा। गौर ए बज़्म है कि शिक्षा जरूरी है बनिस्बत जान जोखिम में डालकर कतई नहीं होनी चाहिए।

सेहत बिगड़ने पर कौन जिम्मेदार ?

सरकार के 16 जून को स्कूल खोलने के रवैये को लेकर अभिभावकों में भारी गुस्सा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को शिक्षा दिलाने के भागमभाग में अधिकतर पालक बच्चों को हरसंभव स्कूल भेज देंगे, वहीं अज्ञानवश बच्चे भी स्कूल चले जायेंगे, बनिस्बत गर्मी की वजह से किसी बच्चे की सेहत खराब हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या स्कूल शिक्षामंत्री या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेंगे?

पंखे हैं तो निर्बाध बिजली नहीं

प्रशासन ने स्कूलों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी स्कूलों में न तो पंखे ठीक से चलते हैं और न ही बिजली की निर्बाध आपूर्ति है। सर्वविदित है कि अघोषित विद्युत कटौती ग्रामीण छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। ऐसे में बच्चों को ठंडे पेयजल तथा ओआरएस की सुविधा मिलने की उम्मीद तो बेमानी सी लगती है।

शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की स्थिति

उमस भरे मौसम में बच्चों को कक्षाओं में बिठाना उनकी एकाग्रता बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक व मानसिक तौर से प्रताड़ित करने के समान होगा। स्कूल में उमस भरे मौसम में बच्चों में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, वहीं अनेक सरकारी स्कूलों में पीने के साफ पानी तक की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, ऐसे में बच्चों के बेहोश होने के आसार बनते हैं। सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों का निरीक्षण

गरियाबंद। विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र के अधिसूचना के तहत जिले में स्कूल बसों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया।

स्कूल बसों के लिए निर्धारित सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं परमिट शर्तों के अनुरूप परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं जिला सेनानी कार्यालय के संयुक्त टीम द्वारा स्कूल बसों की जांच की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पंजीकृत कुल 75 स्कूल बसों में से 30 बसों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। वहीं जिला सेनानी कार्यालय द्वारा बसों में लगे अग्निशमन यंत्रों के उपयोग एवं आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। परिवहन विभाग द्वारा बसों के सभी

आवश्यक दस्तावेजों जैसे प्रदूषण प्रमाण पत्र, कर (टैक्स), बीमा, फिटनेस तथा परमिट दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 45 बसें अनुपस्थित रहने पर स्कूल बसों के संचालकों को नोटिस जारी किया गया गया।

भीषण गर्मी में राहगीरों को मठा, छाछ वितरण

धमतरी। आस्था मंच, धमतरी औषधी विक्रेता संघ व मां आंगर मोती गौ धाम के सदस्यो द्वारा पुरुषोत्तम मास व भीषण गर्मी से बचने हेतु अम्बेडकर चौक माही मेडिकल के पास बस्तर रोड मे आने जाने वाले राहगीरो को मठा, छाछ वितरण किया गया। इस छाछ वितरण मे शहर के समाज सेवी दिलीप बड़जात्या, जानकी गुप्ता, राजेश साहु, अमित अग्रवाल, सत्तु वर्मा,

संजु जैन, कुसुम साहु, गीता साहु, उषा साहु, नेहा साहु, माही साहु, दीक्षा साहु, मौली साहु, नरेन्द साहू, अनिल पिजानी, महक पिंजानी ने आने जाने वाले राहगीरो को छाछ मठा देकर अपनी सेवा दिए।

दृष्टिबाधित, सामान्य विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का सशक्त माध्यम बनेगा ऑडियो बुक्स

धमतरी। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ ने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों तथा सामान्य बच्चों के लिए 10,000 ऑडियो बुक्स निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की दिशा में टीम ने अब तक 9700 से अधिक ऑडियो बुक्स तैयार कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। यह प्रेरणादायक कार्य राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षिका के शारदा जो कि स्वयं दिव्यांग हैं और कमर से नीचे तक 80 प्रतिशत दिव्यांग होने के बावजूद यह नेक कार्य उनके नेतृत्व में संपादित किया जा रहा है। उन्होंने स्वयं 1500 से अधिक आडियो बुक निर्माण किया तथा इस कार्य में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के 30 समर्पित शिक्षक-शिक्षिकाएँ शामिल हैं, जो अपने नियमित शैक्षणिक दायित्वों

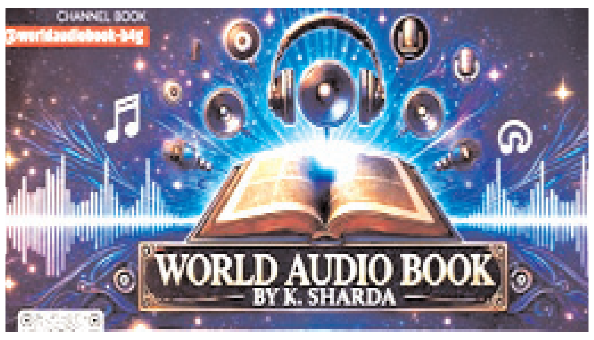

के साथ ही शाला समय के बाद विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण ऑडियो सामग्री तैयार करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं।

इन ऑडियो बुक्स के माध्यम से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री सहज रूप से उपलब्ध हो रही है, वहीं सामान्य बच्चे भी सुनकर सीखने की आधुनिक पद्धति का लाभ उठा रहे हैं। यह पहल शिक्षा को अधिक समावेशीए सुलभ और तकनीक-सम्मत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।विशेषज्ञों के अनुसार ऑडियो बुक्स न केवल विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें कहीं भी और कभी भी अध्ययन करने की सुविधा भी प्रदान करती हैं। वर्ल्ड ऑडियो बुक टीम द्वारा किया जा रहा यह प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को भी साकार करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। के शारदा ने बताया कि टीम का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सामग्री पहुँचाना है, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा उसकी शारीरिक या अन्य सीमाओं के कारण बाधित न हो। उन्होंने बताया कि टीम शीघ्र ही 10,000 ऑडियो बुक्स के लक्ष्य को पूर्ण कर लेगी। वर्ल्ड आडियो बुक चैनल में 2100 से अधिक सब्स्क्राईबर, 107 से अधिक प्लेलिस्ट तथा 700000 से अधिक व्यूज देखे जा सकते हैं। शिक्षा जगत में इस कार्य की व्यापक सराहना की जा रही है। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों ने टीम के प्रयासों को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वर्ल्ड आडियो बुक टीम छत्तीसगढ़ का यह नेक कार्य प्रशंसनीय है।

वरिष्ठजनों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर : रामू रोहरा

नगर पंचायत आमदी में प्रबुद्धजन सम्मान एवं जनसंपर्क अभियान सम्पन्न

धमतरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत नगर पंचायत आमदी में व्यापक जनसंपर्क एवं सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामू रोहरा महापौर नगर पालिका निगम धमतरी रहे जिनके द्वारा शिवप्रसाद साहू सरस्वती शिशु मंदिर जमीन दान किया है एवं भूनु साहू गायत्री परिवार, हेमनु कुंभकार रामायनी, बिसु राम पटेल, मंसा राम साहू, पुरुसोत्तम साहू रिटायर शिक्षक, कैलू पाडे, घासी ढीमर रिटायर पुलिस, नोगेंद्र चक्रधारी धार्मिक जस झांकी आयोजनकर्ता, इन सभी प्रबुद्धजनों का श्री फल और गमछा भेंट कर स्वागत अभिन्दन किया गया। रामू रोहरा ने आगे कहा कि विशेष जनसंपर्क अभियान

केवल सरकार की उपलब्धियों को बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज के वरिष्ठजनों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं अनुभवी व्यक्तियों के आशीर्वाद और सुझाव प्राप्त करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर है, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर तेजराम साहू भाजपा प्रदेश झुग्गी झोपडी सदस्य, ज्योति साहू अध्यक्ष नगर पंचायत आमदी, जीतेन्द्र कुमार पटेल भाजपा जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा, कोमल देवांगन महामंत्री आमदी मंडल, कोमल यादव उपाध्याक्ष, उमानंद कुंभकार सभापति, चन्द्रखेखर साहू कृषि सहकारी समिति अध्यक्ष, त्रिभुवन मटियारा पार्षद, नारायण मटियारा पार्षद, लक्ष्मी जीतेन्द्र पटेल पार्षद, जगेश्वर नेताम पार्षद, सुनीता कृपाल साहू पार्षद, संतोषी आंनद साहू पार्षद, किरण साहू पार्षद, वरिष्ठगण असरु साहू, नीलकंठ साहू, जागेश्वर साहू, आंनद साहू, जिनेंद्र पटेल महामंत्री भाजयुमो आमदी मंडल, तरुण साहू, भेवेन्द्र साहू, मितेश साहू, दीनदयाल साहू, सुरेंद्र पटेल, टूमेन्द्र कोसरिया, प्रेम डीमर एवं जेष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु व नगर वासी मौजूद रहे।

बिजली का झटका, आम जनता पर महंगाई की एक और मार : मोक्ष प्रधान

भंवरपुर। बसना विधानसभा के सक्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य मोक्ष कुमार प्रधान ने संभावित बिजली दर वृद्धि को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल और कृषि से जुड़े आवश्यक संसाधनों की बढ़ती कीमतों के बाद अब बिजली बिल में भी बढ़ोतरी की खबर आम लोगों और किसानों के लिए चिंता का विषय है। मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि यदि जुलाई से बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि लागू होती है, तो इसका सीधा असर मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों, छोटे व्यापारियों और किसानों की जेब पर पड़ेगा। पहले से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ घरेलू बजट को और प्रभावित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिक पहले ही रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं और अब बिजली की संभावित महंगाई से लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उनके अनुसार, महंगाई का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायी इसकी चुनौती का सामना कर रहे हैं। मोक्ष कुमार प्रधान ने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे आम जनता को राहत मिले। उन्होंने मांग की कि बिजली दरों में किसी भी प्रस्तावित वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सिंचाई, छोटे उद्योग और घरेलू उपभोक्ता बिजली पर निर्भर हैं, इसलिए दरों में वृद्धि का व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।

शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर और रेडक्रॉस ने बाजी मारी

धमतरी। हिमाचल प्रदेश की शिमला में आल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहिताश गौर भाभी घर पर हैं फेम, उपाध्यक्ष रेखा गौर के संयोजन में आयोजित 71वें अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता जिसमें देशभर के 29 नाटक एवं सैकड़ों नृत्य शामिल हुए, उक्त महोत्सव में शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर ग्रुप और रेडक्रास धमतरी के कलाकारों और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉ चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और आकाश गिरी गोस्वामी द्वारा निर्देशित औचित्य नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक की कथानक ने शिमला के ऐतिहासिक थिएटर हॉल गेयटी में उपस्थित प्रबुद्ध दर्शकों, निर्णायकों और वरिष्ठ रंगकर्मियों को गहराई से प्रभावित किया। यह कथा एक युवा रंगकर्मी की अंतःखोज को दर्शाती है, जो रंगमंच के माध्यम से देश की समृद्ध ज्ञान, परंपरा, उपनिषदों, वेदों, गीता और महाभारत के शाश्वत गूढ़ प्रश्नों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना चाहता है। नाटक में वैचारिक संघर्ष, आपसी समझ और अंततः आत्मबोध की यात्रा को बेहद मार्मिक, कलात्मक और संवेदनशील ढंग से पिरोया गया, जिसने जजों का दिल जीत लिया। इसके अतिरिक्त, दल द्वारा सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देते हुए संदेशप्रद नुक्कड़ नाटक अंगदान महादान और नशे की विभीषिका पर प्रहार करता नाटक नशा नाश की जड़ है.. का भी अनेक जगहो मे भव्य मंचन किया गया। इन प्रस्तुतियों ने सामाजिक संदेश देने के साथ ही स्थानीय समुदायों में जनचेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कीं। नाटक में शास्त्री की भूमिका में आकाशगिरी गोस्वामी, गांधारी व शास्त्री की पत्नी के रूप में वंदना गोस्वामी, विद्यार्थी व मैनेजर के

रूप में दुष्यंत सिन्हा और नरेंद्र व कृष्ण के रूप में आशीष साहू ने अपने सजीव अभिनय से समां बांध दिया। वहीं हरीश सिन्हा ने रोमियो व अर्जुन, गामिनी ने जुलियट, सुरेश दास मानिकपुरी ने धृतराष्ट्र व योगी और मैकल साहू ने संजय व गाइड मे अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा की छटा बिखेरी। नाटक के संगीत संयोजन ने प्रस्तुति में प्राण फूंकने का काम किया, जिसका जिम्मा आशीष साहू ने बखूबी संभाला। संगीत संचालन वैष्णवी साहू और प्रकाश संचालन मनीष कोटवानी द्वारा किया गया। मेकअप आकाश गिरी वंदना गिरी गोस्वामी ने किया, जबकि वेशभूषा की कमान वीरेंद्र कुंजाम ने संभाली। मंच सज्जा दिव्या साहू और दुष्यंत कुमार के संयुक्त प्रयासों से पूर्ण हुई। उक्त नाटक को कंसोलेशन अवॉर्ड प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि पर शाश्वत उत्सर्ग थियेटर के समस्त कलाकार एवं रंगकर्मी कुमेश्वर कुमार, पीबी पराड़कर, गोपाल शर्मा, दीपक लखोटिया, दीप शर्मा, मदनमोहन खंडेलवाल, डॉ सीएस चौबे, डॉ श्रीदेवी चौबे, डुमन लाल ध्रुव, प्रभा श्रीवास्तव, डॉ सरिता दोशी, कामिनी कौशिक, डॉ प्रदीप साहू, मदन मोहन दास, उमेश सिंह वशिष्ठ, वीरेन्द्र साहू, रविकांत गजेंद्र, मदन सिन्हा, मनुराज पचौरी, दीपाली कलिहारी, शशि हैवार, खिलेंद्र साहू, गुलशन यादव, सुनील शाह, भूषण पटेल, ओमन लाल सिन्हा, हीरालाल साहू, गुलशन ध्रुव, ग्रेवेंद्र सिंह कामड़े, नटवर कन्नौजे, देव शंकर देव, लक्की रजक, वेद साहू, नवीन सोनी, लक्ष्मण साहू, टिक्की निर्मलकर, रेडक्रॉस प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बी एक्का, सचिव डॉ यू एल कौशिक, चेयरमेन प्राप्ति वाशानी, वॉयस चेयरमेन शिवा प्रधान, जिला रेडक्रॉस अधिकारी मनोज साहू, सहायक जिला रेडक्रॉस अधिकारी सत्यप्रकाश प्रधान, अवध राम साहू, जिला सदस्य हेमराज सोनी, गुरशरण साहू, डी एन साहू, डॉ गणेश प्रसाद, परमेश्वर साहू, खूबलाल साहू, खोमन लाल साहू, एल के साहू, मोहिनी साहू, रितु प्रधान, गजानंद साहू, शेषनारायण गजेंद्र, सुरेश साहू, भूपेंद्र दास मानिकपुरी, रामकुमार विश्कर्मा, रामसिंह मांडवी, वेदप्रकाश सिन्हा, जनप्रतिनिधियों, साहित्यकारों, रंगप्रेमियों, रेडक्रॉस टीम और प्रबुद्ध नागरिकों ने पूरी टीम को बधाई दी है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव का रंजना साहू ने जताया आभार

डिपोपारा सामुदायिक भवन हेतु राशि स्वीकृत

धमतरी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धमतरी की पूर्व विधायक रंजना डीपेंद्र साहू की अनुशंसा एवं सतत प्रयासों से धमतरी नगर निगम क्षेत्र के सोरिद वार्ड स्थित डिपोपारा सामुदायिक भवन के विकास कार्यों के लिए 15 लाख 97 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस स्वीकृति से क्षेत्र के नागरिकों को सामुदायिक भवन में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्वीकृत राशि से सामुदायिक भवन परिसर में बोर खनन, शौचालय निर्माण, बाउंड्रीवॉल तथा शेड निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए जाएंगे। इन सुविधाओं के विकसित होने से भवन का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए

और अधिक सुविधाजनक एवं उपयोगी हो सकेगा। रंजना साहू ने बताया कि डिपोपारा क्षेत्र के रहवासियों द्वारा लंबे समय से सामुदायिक भवन में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की मांग की जा रही थी। क्षेत्रवासियों की इस आवश्यकता को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने शासन स्तर पर विषय को प्रमुखता से रखा और लगातार प्रयास किए, जिसके परिणामस्वरूप यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि अपने विधायक कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्रवासियों को सामुदायिक भवन की सौगात दी थी और अब उसके विकास एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। डिपोपारा सामुदायिक भवन में होने वाले विकास कार्य भी इसी जनहितकारी सोच का परिणाम हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साहू ने कहा कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड और गांव में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वे सदैव प्रतिबद्ध हैं।

विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने पर नगर निगम सभापति कौशिल्या देवांगन, पार्षद विजय मोटवानी, पार्षद निलेश लुनिया, पूर्व पार्षद रितेश नेताम, अंकालू सिन्हा, पीताम्बर साहू, कांशी राम साहू, पंकज गौतम, चंद्रहास सेन, रेखा, तारा सेन, हिमांशु साहू एवं राम सिन्हा सहित वार्डवासियों ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना डीपेंद्र साहू तथा प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किए।

शाला प्रवेश उत्सव पर चल संगी स्कूल जाबो गीत एवं एल्बम का विमोचन

भंवरपुर। शाला प्रवेश उत्सव 2026 हेतु स्कूल शिक्षा विभाग महासमुंद में पदस्थ शिक्षकों द्वारा एक शानदार पहल करते हुए छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने हेतु चल संगी स्कूल जाबो गीत एवं एल्बम को विधानसभा बसना विधायक संपत अग्रवाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द बी एल देवांगन डी एम सी रेखराज शर्मा सहायक संचालक एन के सिन्हा प्रमोद कुमार कन्नौजे एवं प्रकाश मांझी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विधायक विधानसभा बसना संपत अग्रवाल ने कहा कि इस गीत में सरकारी स्कूलों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के साथ-साथ बच्चों को छत्तीसगढ़ एवं संपूर्ण देश के लिए तैयार होने एवं अपना सर्वांगीण विकास करने हेतु प्रेरित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द बी एल देवांगन ने अपने नवाचारी शिक्षकों के टीम को

बधाई देते हुए कहा कि हम सभी का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ना एवं उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करना है समाज के प्रत्येक अंग जिसमें जनप्रतिनिधि पालक शिक्षक सभी को मिलकर पूरे जिले में हमें 100% बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन देना है तथा ड्रॉप आउट को भी शून्य करना है। समग्र शिक्षा जिला महासमुंद के डी एम सी रेखराज शर्मा ने अपने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे सभी कार्य जो हमारे बच्चों को एवं पालक बंधुओं को विद्यालय के विकास से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे हैं वे स्वागत योग्य हैं हम सभी का उद्देश्य बच्चों की 100त्न एडमिशन के साथ बच्चों को बेहतरीन शिक्षा एवं पोषण देना है हम सभी को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य हैं वह जितने आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे हमारा राष्ट्र भी उतना आगे बढ़ेगा एवं मजबूत होगा। इस एल्बम की प्रस्तुति एवं संयोजन महासमुंद जिले के शिक्षकों वीरेंद्र कर प्रदीप क्षत्रे शैलेंद्र नायक सोमदेव तिवारी पूनम साहू एवं गिरधारी साहू ने किया है। इस गीत के गीतकार वीरेंद्र कर एवं शैलेंद्र नायक हैं। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि इस एल्बम का उद्देश्य 100% बच्चों को स्कूल से जोड़ना और उनके सर्वांगीण विकास में सहभागिता रखना है शैलेंद्र नायक जी ने बताया कि पालकों को अधिक से अधिक प्रेरित कर अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु स्कूली योजनाओं को उन्हें बताते हुए स्कूल से जोड़ना है इस गीत को मधुर स्वर से प्रदीप क्षत्रे शैलेंद्र नायक वीरेंद्र कर पूनम साहू एवं गिरधारी साहू ने सजाया है साथ ही साथ सोमदेव तिवारी एवं प्रदीप छत्रे ने मधुर संगीत वादन के रूप में हारमोनियम वादन एवं तबला वादन किया है। इस कार्य हेतु जिले के समस्त जन प्रतिनिधियों अधिकारियों एवं शिक्षकों द्वारा अपने इन होनहार शिक्षकों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई है।

संपादकीय

लोकतंत्र एक मजबूत विपक्ष के मुखर स्वर से ही जीवित रहता है

माना जा रहा था कि कुछ दलों की नाराजगी का असर बैठक पर पड़ सकता है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले दलों के बीच कई मुद्दों पर साझा अभियान चलाने पर सहमति बनी। इसमें कोई दोराय नहीं कि विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के सामने फिलहाल बहुस्तरीय चुनौतियां खड़ी हैं और संगठित होकर इनका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मगर पिछले कुछ समय से 'इंडिया' के कुछ घटकों ने गठबंधन के दायित्वों से जुड़े जैसे सवाल उठाए हैं, उन पर विचार करके आगे की दिशा तय करने की चुनौती शायद सबके लिए अहम है।गौरतलब है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों और उसके बाद नीट-यूजी 2026 के प्रश्नपत्र लीक होने सहित कई व्यापक महत्त्व के मुद्दों पर जनता के भीतर असंतोष के स्वर तीखे होने के बीच सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन की बैठक हुई। माना जा रहा था कि कुछ दलों की नाराजगी का असर बैठक पर पड़ सकता है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले दलों के बीच कई मुद्दों पर साझा अभियान चलाने पर सहमति बनी।मुख्य रूप से एसआइआर और चुनावों में वोटों की गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सभी दल सहमत थे। नाजुक आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई और समाज के कमजोर तबकों के मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की गई।हालांकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस ने जिस तरह सत्ता में आई टीवीके के साथ नया मोर्चा बना लिया, उसके बाद द्रमुक का 'इंडिया' में साथ रहना वैसे भी मुश्किल था। इसी तरह, माकपा ने भी केरल में चुनाव के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया।मतभेद के मुद्दों पर संवाद और एक-दूसरे को समान स्तर पर अहमियत देना गठबंधन को मजबूत करने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इसके सभी सदस्य-दलों के भीतर सामूहिक भावना के साथ राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की इच्छाशक्ति हो।जिस समय राजनीतिक चुनौतियां गहरा रही हों, वैसे में साझा मोर्चा मजबूत करने का रास्ता निकालने के लिए न्यूनतम बिंदुओं पर सहमति के रास्ते तैयार करने की जरूरत है। लोकतंत्र एक मजबूत विपक्ष के मुखर स्वर से ही जीवित रहता है। ऐसे में कुछ मतभेदों के बावजूद 'इंडिया' गठबंधन में शामिल दलों के बीच नए सिरे से मैदान में उतरने और हर दो महीने में बैठक करने पर बनी सहमति शायद वक्त का तकाजा भी है।

12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी आग में 17 लोगों की जान गई। जांच में सामने आया कि होटल में अवैध निर्माण हुआ था और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। 2022 में मुंडका की व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। वहां भी केवल एक निकास मार्ग था और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। पिछले दिनों दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे यहां हादसे अचानक नहीं होते बल्कि उन्हें पैदा किया जाता है।

बेगुनाह जिंदगियों से खेलता भ्रष्ट तंत्र और दिल्ली के अंतहीन अग्निकांड

(योगेश कुमार गोयल)

21 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों घायल, धुएं में घुटती सांसें, तीसरी मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगाते लोग और बेसमेंट के बाहर बंद पड़ा निकास द्वार, यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता, भ्रष्ट व्यवस्था और नियमों की खुलेआम हत्या का भयावह परिणाम था। दुखद यह है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली बार-बार अग्निकांडों में जलती है, लोग बार-बार मरते हैं, जांच समितियां बनती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मालवीय नगर के हादसे में जो शुरुआती तथ्य सामने आए, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। जिस भवन में 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' और 'मिकासा होम्स' संचालित हो रहे थे, वहां कथित रूप से छह कमरों की अनुमति के बावजूद 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। भवन से निकलने का केवल एक रास्ता था। बेसमेंट में लोगों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी गेट पर ताला लगा था। आग लगने के बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग बाहर निकल ही नहीं सके। कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। यह दृश्य 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड की भयावह यादों को फिर से ताजा कर गया, जहां बाहर निकलने के रास्ते बंद होने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी।

दिल्ली में अग्निकांडों का इतिहास बताता है कि हर बड़ी त्रासदी के पीछे कहानी लगभग एक जैसी है, अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाणपत्र, बंद निकास द्वार और प्रशासनिक लापरवाही। 13 जून 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी, जो दिल्ली का अब तक का सबसे भयावह अग्निकांड माना जाता है। आग लगने के बाद सिनेमा हॉल में धुआं भर गया और निकास मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने की बातें तो बहुत हुई लेकिन वास्तविकता यही है कि उनसे कोई स्थायी सबक नहीं लिया गया। 31 मई 1999 को लाल कुआं स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग में 57 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी अवैध गोदामों और रासायनिक इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया गया। 8 दिसंबर 2019 को अनाज मंडी की अवैध फैक्टरी में लगी आग में 43 लोगों की मौत हुई। उस समय

भी खुलासा हुआ था कि इमारत में निकास के पर्याप्त रास्ते नहीं थे, सीढ़ियां सामान से भरी थी और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिलें लगी थी। जहरीले धुएं ने मजदूरों को सोते हुए ही मौत की नींद सुला दिया।

12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी आग में 17 लोगों की जान गई। जांच में सामने आया कि होटल में अवैध निर्माण हुआ था और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। 2022 में मुंडका की व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। वहां भी केवल एक निकास मार्ग था और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। उसी वर्ष गोकुलपुरी की झुग्गी बस्ती में आग से 7 लोगों की जान चली गई। 2024 में अलीपुर की अवैध पेंट फैक्टरी में लगी आग में 11 लोगों की मौत हुई। 2026 में पालम और विवेक विहार में हुए अग्निकांडों में नौ-नौ लोगों की जान गई। अब मालवीय नगर की त्रासदी ने मृतकों की सूची में 21 और नाम जोड़ दिए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2026 से 27 मई 2026 तक आग की घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद विवेक विहार और मालवीय नगर की घटनाओं को जोड़ दें तो यह संख्या 67 से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि उन परिवारों की बर्बादी का दस्तावेज है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी इमारतें बन कैसे जाती हैं? कैसे आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलने लगती हैं? कैसे छह कमरों की अनुमति वाले भवन में 25 कमरे बन जाते हैं? कैसे फायर एनओसी के बिना होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां वर्षों तक संचालित होती रहती हैं? कैसे चार मंजिल की अनुमति वाले क्षेत्र में छह-सात मंजिलें खड़ी हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब किसी जांच आयोग की मोटी रिपोर्ट में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की उस जड़ में छिपा है, जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। यदि कोई अवैध इमारत बनती है तो वह एक दिन में नहीं बनती। उसकी नींव पड़ती है, दीवारें उठती हैं, मंजिलें तैयार होती हैं, बिजली के कनेक्शन लगते हैं, पानी के कनेक्शन मिलते हैं और फिर व्यापार शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक सरकारी विभागों की आंखों के सामने सब कुछ होता है। इसलिए यह कहना कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी, वास्तविकता से आंखें मूंदना होगा। सच यह है कि ऐसी अधिकांश इमारतें प्रशासन और कारोबारियों की मिलीभगत का परिणाम होती हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जांच के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणाएं होती हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बड़े अधिकारी को कठोर दंड मिला? क्या कभी किसी विभागीय प्रमुख को जवाबदेह ठहराया गया? क्या कभी ऐसी कार्रवाई हुई कि भविष्य में कोई अधिकारी नियमों की अनदेखी करने का साहस न कर सके? दुर्भाग्य से जवाब है 'नहीं'। मालवीय नगर का हादसा भी केवल एक होटल या रेस्टोरेंट की कहानी नहीं है। यह उस पूरे शहरी विकास मॉडल पर प्रश्नचिह्न है, जहां मुनाफा मानव जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं, जहां फायर सेफ्टी के उपकरण या तो हैं ही नहीं या केवल दिखावे के लिए लगाए गए हैं। अनेक भवनों में इमरजेंसी एग्जिट कागजों में मौजूद हैं लेकिन वास्तविकता में बंद पड़े हैं। कई जगहों पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग की बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। संकरी गलियों में बहुमंजिला भवन खड़े हैं, जहां दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती।

अब समय आ गया है कि केवल जांच और मुआवजे की राजनीति से आगे बढ़ा जाए। दिल्ली में सभी होटलों, गेस्ट हाउसों, रेस्टोरेंटों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों और बहुमंजिला इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। फायर एनओसी की व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी बने। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना नहीं बल्कि तत्काल ध्वस्तीकरण हो। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले भवन मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या नहीं बल्कि कठोर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। जब तक जवाबदेही की तलवार ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक नीचे कोई नहीं सुधरेगा। मालवीय नगर की आग में मारे गए लोग किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं थे, वे आम नागरिक थे, जिनमें महिलाएं थी, विदेशी नागरिक थे, मरीजों के परिजन थे और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर वहां ठहरे हुए लोग थे। आज जरूरत शोक व्यक्त करने से ज्यादा आत्ममंथन की है। उपहार कांड से लेकर मालवीय नगर तक लगभग तीन दशक बीत चुके हैं लेकिन व्यवस्था की मानसिकता नहीं बदली। यदि इस बार भी कुछ दिनों के शोर-शराबे के बाद सब कुछ सामान्य हो गया तो यकीन मानिए, अगला अग्निकांड केवल समय का प्रश्न होगा। तब फिर वही सवाल गूंजेगा कि आखिर बेगुनाह लोगों की जान से खेलते इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? (लेखक 36 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार और 'सागर से अंतरिक्ष तक- भारत की रक्षा क्रांति' सहित कई चर्चित पुस्तकों के लेखक हैं)(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दहलीज़ लांघती बेटियां, स्कूल बैग से ज़्यादा भारी है सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ

(अतुल मौर्य)

भोर की पहली धूप के साथ जब लड़कियाँ घर की देहरी लाँघती हैं, तो उनके कंधों पर स्कूल बैग से कहीं अधिक भारी बोझ होता है। राजस्थान के एक छोटे कस्बे की प्रिया हो, या दिल्ली के किसी सरकारी विद्यालय की रोशनी; सुबह छह बजे उठकर, रसोई में चाय बनाकर, छोटे भाई-बहनों को तैयार करके जब वे बस की ओर दौड़ती हैं, तो यह दौड़ केवल विद्यालय तक नहीं होती। वे उस संसार में कदम रखती हैं जो उनसे कहता है- प्रश्न करो, आत्मविश्वास रखो, अपने सपनों को नाम दो।

कक्षाओं में वे संविधान की समता पढ़ती हैं, विज्ञान में तर्क के सूत्र सीखती हैं, भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को धार देती हैं। परंतु संध्या की छाया के साथ जब वही लड़कियाँ घर की ओर लौटती हैं, तो वे एक बिल्कुल भिन्न दुनिया में प्रवेश करती हैं।

यह दुनिया किताबों की भाषा नहीं बोलती। यहां आवाज़ का तेज़ होना असंस्कार माना जाता है, हँसी की ऊँचाई मापी जाती है। एक ओर कक्षा में शिक्षिका कहती हैं- बेटा, बोलो, संकोच मत करो; दूसरी ओर घर में दादी टोकती हैं- इतनी ज़ोर से हँसते नहीं, लड़की हो। यही वह अदृश्य विभाजन रेखा है जिसे हम प्रायः दैनंदिन जीवन की सामान्यता मानकर अनदेखा कर जाते हैं।

स्वीकृति के भीतर की अदृश्य सीमा

समाज अब लड़कियों की पढ़ाई का उस तरह विरोध नहीं करता जैसा कभी करता था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -5) के अनुसार देश में 15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं में साक्षरता दर 90 प्रतिशत तक पहुँच गई है यह निस्संदेह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। किंतु इस स्वीकार्यता की परतों के नीचे भी एक अदृश्य रेखा खिंची रहती है। मार्च 2025 में बिहार के दानापुर की खुशबू कुमारी की कहानी पूरे देश ने देखी, जिसने कक्षा 10 में 500 में से 399 अंक लाए, पर परिवार ने विज्ञान की जगह कला वर्ग में दाखिला दिलाया। खुशबू डॉक्टर बनना चाहती थीं।

यह कोई अपवाद नहीं है। (उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट) 2022-23 के आँकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन अनुपात बढ़ा है, परंतु इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान में उनकी उपस्थिति अभी भी एक-तिहाई से कम है। शिक्षण, परिचर्या और मानविकी, ये क्षेत्र इसलिए सामाजिक रूप से मान्य हैं क्योंकि इनमें देखभाल और सेवा का भाव दिखता है और समाज स्त्री को इन्हीं भावों से जोड़कर देखने का आदी है।

अभियांत्रिकी, न्यायशास्त्र, राजनीति, रक्षा-सेवाएँ या वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में जाने वाली लड़कियाँ अभी भी सामाजिक कल्पनाशीलता की परिधि से बाहर हैं। जो इन क्षेत्रों की ओर जाती हैं, उन्हें प्रत्यक्ष प्रतिबंध से अधिक सूक्ष्म असहजताओं से गुजरना पड़ता है जैसे कि सेना में जाओगी, फिर शादी कौन करेगा? या वकालत में घर कब सँभालोगी? जैसे प्रश्न उनके सपनों को 'यथार्थ' की कसौटी पर बार-बार परखते हैं। धीरे-धीरे लड़की स्वयं भी यह आत्मसात करने लगती है कि उसके सपनों की एक 'सामाजिक सीमा' है। उसे आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है परंतु केवल उतनी, जितनी से स्थापित सामाजिक संरचना असहज न हो।

शिक्षाशास्त्री प्रो. कृष्ण कुमार की दृष्टि में समाज स्त्री को केवल विधि-निषेधों से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संकेतों की एक सूक्ष्म भाषा से गढ़ता है। पहनावा, चाल, आवाज़ का आरोह-अवरोह इत्यादि, ये सब मिलकर एक अघोषित पाठ्यक्रम रचते हैं। इसकी अभिव्यक्ति कभी-कभी बेहद ठोस होती है। दिल्ली के कुछ विश्वविद्यालयों में एक शोध के दौरान छात्राओं से पूछा गया कि वे कक्षा में प्रश्न पूछने से क्यों हिचकती हैं।

उत्तर चौंकाने वाले थे कि लड़के हँसते हैं, प्राध्यापक सीरियसली नहीं लेते, घर में माँ कहती हैं ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं। ये तीनों उत्तर तीन अलग-अलग दुनियाओं से आए थे परंतु एक ही निष्कर्ष पर मिलते थे = तुम्हारी आवाज़ का एक निर्धारित दायरा है। शायद इसीलिए बहुत-सी लड़कियाँ कम आयु में ही दो भिन्न संसारों के बीच एक अदृश्य सेतु बनाना सीख लेती हैं। विद्यालय में वे आत्मविश्वास से बोलती हैं, घर में संयम धारण करती हैं। वे जानती हैं कि किस परिसर में कितनी हँसी स्वीकार्य है, और कहाँ मौन ही समझदारी है। मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को 'कोड-स्विचिंग' कहता है। कोड-स्विचिंग वह मानसिक श्रम है जो व्यक्ति को एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में जाते ही अपना व्यवहार, भाषा और अभिव्यक्ति बदलनी पड़ती है। यह श्रम अदृश्य है, थकाने वाला है, और अनिवार्यतः असमान क्योंकि यह लड़कियों से ही अपेक्षित है, लड़कों से नहीं।

नरेंद्र मोदी के 12 साल- भरोसे के हकीकत में बदलने का दौर

खैर यह सब होते हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन के बावजूद पेयजल की सहज उपलब्धता, खेती की बरसात पर निर्भरता, परिसीमन आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ठोस काम किया जाना है।

यदि मॉर्निंग कंसल्ट की माने तो दुनिया के नेताओं की सूची पर एक नजर दौड़ाई जाएं तो कोई भी वैश्विक नेता स्वीकार्यता में नरेन्द्र मोदी के आसपास भी नहीं टिकते।

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

विपक्षी पार्टियां द्वारा लगातार देश और विदेश में अभियान चलाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रेंकिंग या स्वीकार्यता के मामलें में वैश्विक नेताओं से बहुत आगे हैं। 68 प्रतिशत स्वीकार्यता नरेन्द्र मोदी की है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार्यता रेंक लगातार नेगेटिव जा रही है। फालोवर्स में भी नरेन्द्र मोदी सबसे आगे हैं। दुनिया का संभवतः हमारा ही देश होगा जहां देश के बाहर भारत की छवि खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह स्वीकार्यता निश्चित रुप से भारत ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी उनकी लोकप्रियता और सर्वमान्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले चुनिंदा प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुनिंदा इसलिए कि देश में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए पर पं. नेहरु 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री रहे। लगातार 12 साल कोई कम नहीं होते और वह भी लगातार 12 साल। सबसे बडी बात यह कि इस दौरान नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा ऐसे साहसिक निर्णय किये गये हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। माना तो यही जाता था कि कश्मीर में धारा 370 और 35 ए हटाना, राममंदिर का निर्माण, डिजिटल क्रांति, वैश्विक नेतृत्व, नोटबंदी, एक देश एक कर, घर घर शोचालय, घर घर कचरा संग्रहण, रक्षा उपकरणों का निर्यात, किसान सम्मान, मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, बड़ी अर्थ व्यवस्था, तेजी से ढांचागत विकास, डिजिटल भुगतान, नक्सलवाद की नेस्तनाबूदी, आत्मनिर्भर भारत, परिवहन क्षेत्र में ढांचागत बदलाव आदि आदि समय समय पर की जाने वाली घोषणाएं केवल चुनाव जीतने के जुमले हैं पर लगभग असंभव माने जाने वाले यह काम आज धरातल पर उतरना सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जा सकती है। इससे सबके साथ ही सबसे आश्चर्य जनक बात यह है कि लाख विरोध के बावजूद विपक्ष आज हाशिये में चला गया है।

कश्मीर से धारा 370 और 35 ए की समाप्ति हो चुकी है। दुनिया के किसी देश ने खुलकर इसका विरोध करने

की हिम्मत नहीं दिखाई। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राममंदिर का निर्माण हो चुका है तो तीन तलाक, सीएए, यूसीसी और यहां तक कि सर्जीकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिन्दुर तक पर दुनिया के किसी देश की भारत के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हो पाई है। आज अर्थ व्यवस्था में जिस तेजी से बदलाव आया है और चौथी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने के बाद अब तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनने की और तेजी से कदम बढ़ चुके हैं। जनधन योजना के समय जिस तरह से आलोचना का दौर चला था आज भुगतान में डिजिटलीकरण में इसकी बड़ी भूमिका तय हो चुकी है। जो लगभग असंभव माना जा सकता था वह आज डिजिटल भुगतान के माध्यम से संभव हो पाया है और पांच रु. के टमाटर का भुगतान भी सब्जीवाले तक को यूपीआई से आसानी से होने लगा है। सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के भुगतान, पेंशन, अनुदान आदि आज सीधे खातों में जाने लगे हैं। यह किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। आईपीसी सीपीसी में बदलाव किया जा चुका है। तो जीएसटी में लाख कमियां गिनाने के बावजूद आज समूचा देश एक देश एक कर के छाते के नीचे आ चुका है। बुनियादी ढांचें में तेजी से बदलाव आया है। आज वंदे भारत और नमो भारत ट्रेन चलने लगी है तो 33 किमी प्रतिदिन हाईवे का निर्माण हो रहा है। एक्सप्रेस हाईवे से आवागमन आसान हुआ है। आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका है तो सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता का नेटवर्क विस्तारित किया गया है। आज 98 प्रतिशत घरों से घर घर कचरा संग्रहण होने लगा है तो अब घर घर में शोचालय बन चुके हैं। कोरोना के दौरान हमारे प्रयासों को सारी दुनिया द्वारा सराहा गया यहां तक कि कोरोना के दौरान जीवन रक्षक की भूमिका में भारत ने भूमिका निभाई। किसानों की आय में बढ़ोतरी के ठोस प्रयास हुए हैं तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को उनका आत्मसम्मान उपलब्ध कराया गया है। एमएसपी व्यवस्था में सुधार हुए हैं तो खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव छाप दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट भी आज साकार होता दिखाई दे रहा है। आज हम रक्षा उपकरणों का निर्यात करने लगे हैं तो सहस्त्रबलों के आधुनिकीकरण और निर्णय की स्वतंत्रता का परिणाम है कि आज सेनाएं आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रही है। आज देश आत्म निर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जहां तक कूटनीतिक स्तर पर सफलता की बात है तो भारत आज पिछलग्गू देशों में नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाख प्रयासों के बावजूद भारत के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में आज तुरकिया जैसे एकाध को छोड़कर कोई देश बोलने की स्थिति में नहीं है। मालदीव को नरेन्द्र मोदी के एक फोटो ट्वीट ने सबक सीखा दिया तो दूसरे देश भी भारत की ताकत को समझने लगे हैं।

खैर यह सब होते हुए भी नरेन्द्र मोदी सरकार के सामने अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। रोजगार सृजन, प्रति व्यक्ति आय में अंतर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जल जीवन मिशन के बावजूद पेयजल की सहज उपलब्धता, खेती की बरसात पर निर्भरता, परिसीमन आदि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर ठोस काम किया जाना है। देश में जिस तरह से पेपर लीक होने के मामले सामने आये हैं इससे युवाओं में निराशा हुई है उसे दूर करने की चुनौती सामने हैं तो स्टार्ट अप और कौशल विकास के बावजूद बेरोजगारी की दर अभी भी चिंतनीय स्तर पर है। साइबर क्राइम और गेमिंग जैसी नई चुनौतियां तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग के साइड इफेक्ट आदि अनेक समस्याएं समाधान चाहती है। देश आज तेजी से एक देष एक चुनाव के धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहा है। रिन्यूवल एनर्जी पर बहुत कुछ हासिल करने के बावजूद अमेरिका ईरान युद्ध के कारण जिस तरह से तेल और एलपीजी का संकट आया है इसका भी दीर्घकालीन समाधान खोजा जाना है। हांलाकि समस्याएं अनवरत और नियमित प्रक्रिया है पर दीर्घकालीन योजनाओं से आसानी से निपटा जा सकता है।

इस सबके बावजूद देशवासियों को नरेन्द्र मोदी के प्रति पूरा भरोसा है। यही कारण है कि विपक्ष की लाख आलोचनाओं के बावजूद नरेन्द्र मोदी की स्वीकार्यता और भरोसे व उनके आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी नहीं आई है। सौ टके की बात कही जाएं तो नरेन्द्र मोदी की अपार उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां भी अपार है और सबसे अच्छी बात यह कि देशवासियों का उनपर भरोसा भी पूरा है और वैश्विक स्वीकार्यता भी सबसे अधिक है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

संक्षिप्त समाचार

कूलर में पानी भरना पड़ा भारी, करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

रायपुर। गर्मी से राहत देने वाला कूलर एक परिवार के लिए काल बन गया। जशपुर जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के तारागढ़ गांव में करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के मुताबिक, महिला अपने घर में रखे कूलर में पानी भर रही थी। इसी दौरान कूलर में अचानक करंट प्रवाहित हो गया और वह उसकी चपेट में आ गई। करंट इतना तेज था कि महिला खुद को उससे अलग नहीं कर सकी और गंभीर रूप से झुलस गई। घर से चीख-पुकार की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद महिला को कूलर से अलग किया। आनन-फानन में उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल पत्थलगांव ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

24 घंटे के भीतर जेवर समेत दो चोर पहुंचे सलाखों के पीछे

रायपुर। सकरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। इस सफलता में डॉग स्क्वॉड की सूंघने की क्षमता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई निर्णायक साबित हुई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 60 हजार रुपये मूल्य के चोरी गए सोने-चांदी के जेवर बरामद किए हैं।जानकारी के अनुसार, साईं नगर उस्लापुर निवासी नीता बघेल ने 13 जून को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कृष्णा अस्पताल में ड्यूटी के लिए घर बंद कर जाने के बाद अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखे जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सकरी पुलिस सक्रिय हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर विशेष जांच टीम गठित की गई। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, वहीं डॉग स्क्वॉड ने जांच को नई दिशा दी। पुलिस डॉग घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर सीधे साईं नगर क्षेत्र तक पहुंचा, जिससे संदिग्धों की पहचान आसान हो गई। पुलिस ने संदेह के आधार पर विकास चतुर्वेदी (24) और अमन टंडन (20) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों पहले पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन साक्ष्यों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चांदी के पायल, दो कमरबंद, सोने के कान के जेवर, फुल्ली और अन्य चोरी का सामान बरामद कर लिया।

10 महीने बाद पुलिस के शिकंजे में गांजा तस्करी का मास्टर माइंड

रायपुर। अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के खिलाफचलाए जा रहे अभियान में महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 माह से फरार चल रहे गांजा तस्करी के मुख्य आरोपी और वाहन मालिक कंभूपानी बिशोई को ओडिशा के गंजाम जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 190 किलोग्राम गांजा की तस्करी और दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले में आरोप हैं। पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई 2025 को थाना खल्लारी क्षेत्र के हाड़ाबंद ओवरब्रिज के पास एक कार में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा था।

प्रगतिशील किसानों को किया गया सम्मानित

प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपनी बढ़ाएं आय-केदार कश्यप

- खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन
- किसानों को वितरित किए गए उन्नत बीज और प्राकृतिक खेती की सामग्री

रायपुर/ संवाददाता

प्राकृतिक खेती रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करती है, जिससे खेती की लागत में कमी आती है और किसानों की शुद्ध आय बढ़ती है। साथ ही, यह मिट्टी की जैविक विविधता और उर्वरता को पुनर्जीवित करती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि को टिकाऊ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित ष्खेत बचाओ अभियानष् के तहत कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण नागरिकों ने भाग लिया। एक दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी के अवसर पर कृषि, उद्यानिकी, पशुधन विकास, मत्स्य, रेशम विभाग, कृषि महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कृषि नवाचार और आजीविका संवर्धन से संबंधित प्रदर्शनी

लगाई गई। अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर किसानों से संवाद किया और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने किसानों को हल्दी की उन्नत किस्म के प्रकंद, रागी बीज एवं प्राकृतिक खेती में उपयोगी सामग्री का वितरण किया। जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाले प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। मिलियनेयर कृषक अवार्ड से सम्मानित श्री चैतूराम यादव एवं श्री नीलकंठ नाग, बेस्ट फार्मर इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अवार्ड प्राप्त श्री सुरेन्द्र नाग तथा राज्यपाल सम्मान से सम्मानित श्रीमती गीता नाग को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि किसानों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम कर प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण करने और खेती की लागत कम करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने जीवामृत, बीजामृत, प्राकृतिक कीट प्रबंधन तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल देते हुए किसानों को टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर सुश्री नम्रता जैन ने बताया कि खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाकर स्वस्थ और सुरक्षित खाद्य उत्पादन में योगदान देने की अपील की। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों ने जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे प्राकृतिक कृषि उत्पादों के निर्माण एवं उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृषकों, जनप्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों, छात्र-छात्राओं एवं विभागीय अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. दिव्येंदु दास ने सभी अतिथियों और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। यह आयोजन किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक करने, कृषि लागत कम करने, आय बढ़ाने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

सोलर दीदियां बनेंगी हरित ऊर्जा की नई पहचान........

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत कबीरधाम जिले में महिला सशक्तिकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अभिनव पहल की गई है। कबीरधाम जिले में वंदे मातरम् संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों की 35 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं अब गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, संचालन, रखरखाव एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करेंगी। विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में दीदियों को सोलर सिस्टम की तकनीकी बारीकियों, उपकरणों की स्थापना, मरम्मत, रखरखाव तथा उपभोक्ता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के पश्चात सोलर दीदियां गांवों में सौर उपकरणों की स्थापना और मरम्मत का कार्य कर सकेंगी, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत प्राप्त होगा। सौर संयंत्रों की स्थापना पर मिलने वाले कमीशन के माध्यम से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ग्रामीणों को अपने ही गांव में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे स्थापना प्रक्रिया सरल होगी तथा उपकरणों का रखरखाव भी स्थानीय स्तर पर आसानी से हो सकेगा।

महतारी वंदन योजनाः प्रतिमाह मिल रही आर्थिक सहायता....

- लक्ष्मी गंधर्व की छोटी-छोटी जरूरतें हो रही पूरी

रायपुर/ संवाददाता

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना जिले की हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इसी कड़ी में मुंगेली निवासी श्रीमती लक्ष्मी गंधर्व के लिए यह योजना आर्थिक संबल और आत्मविश्वास का माध्यम बन गई है। श्रीमती लक्ष्मी गंधर्व नियमित रूप से महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता

मिल रही है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर पा रही हैं। इस राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू आवश्यकताओं तथा छोटे-मोटे दैनिक खर्चों के लिए कर रही हैं। लक्ष्मी गंधर्व ने बताया कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए आर्थिक सहारा बन गई है। नियमित सहायता मिलने से परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार आया है और आत्मनिर्भर बनने का विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें परिवार के निर्णयों में अधिक भागीदारी और आत्मविश्वास भी दे रही है। लक्ष्मी गंधर्व ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। नियमित आर्थिक सहायता से महिलाओं को अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के निर्माण में मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित फोटो प्रदर्शनी

- सांसद चिंतामणि महाराज ने किया उद्घाटन, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियां प्रदर्शित

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा अम्बिकापुर के कला केंद्र मैदान में आयोजित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ मंगलवार को सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने किया। 16 से 18 जून तक आयोजित इस प्रदर्शनी में केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा देश की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आकर्षक चित्रों और जानकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी शासन की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है। उद्घाटन अवसर पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी नागरिकों को विकास यात्रा और शासन की उपलब्धियों से अवगत कराने का सशक्त माध्यम है। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सरल एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त हो रही है। वहीं जनप्रतिनिधि श्री भारत सिंह सिसोदिया ने भी नागरिकों से प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को चित्रों एवं तथ्यों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही आधारभूत संरचना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है।

अब समय पर खाद बीज मिलने से सियालाल के खेतों में आई समृद्धि

- विष्णुदेव साय सरकार की किसान हितैषी नीतियों से नारायणपुर के भिरागांव में बदला खेती का परिदृश्य, बढ़ी आय

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ सरकार की किसान-कल्याण प्राथमिकताओं का असर अब बस्तर के वनांचल क्षेत्रों में साफदिखने लगा है। जिले में किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से खेती-किसानी का काम बेहद

सुगम हो गया है। इसी का एक जीवंत उदाहरण हैं नारायणपुर जिले के ग्राम भिरागांव के प्रगतिशील किसान सियालाल यादव, जिनके लिए इस वर्ष का खरीफ सीजन नई उम्मीदें और उत्साह लेकर आया है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत समय पर खाद एवं उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध होने से सियालाल बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी आगामी खरीफ सीजन की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए सियालाल बताते हैं कि पहले आवश्यक कृषि सामग्री, खाद और बीज के लिए हम किसानों को भटकना पड़ता था और कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब शासन की सजगता से सब कुछ गांव के नजदीक और समय पर मिल रहा है। इससे न केवल हमारी चिंता दूर हुई है, बल्कि खेती करना पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गया है। किसान सियालाल यादव पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ अब दलहन और मोटे अनाजों (मिलेट्स) को अपनाकर अपनी तकदीर खुद बदल रहे हैं।

जिले में साइंस ऑन व्हील्स का शुभारंभ

रायपुर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकासखंड आरंग के ग्राम राखी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंतरिक्ष केंद्र, रायपुर से राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान जागरूकता अभियान साइंस ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। यह अभियान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (ष्ठस्ञ्ज) के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (ह्रष्टस्ञ्जष्ट) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस पहल को प्लाक्षा विश्वविद्यालय, आईआईटी मंडी तथा इसरो पंजीकृत स्पेस ट्यूटर संस्था द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में छह घंटे का हैंड्स-ऑन विज्ञान प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रॉकेट एवं उपग्रहों की कार्यप्रणाली, भारत के अंतरिक्ष अभियानों, रोबोटिक्स एवं जल संरक्षण, स्वच्छ जल एवं सतत विकास से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र एस.एस. बजाज उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीएसएनएल छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक वी.के. छबलानी, प्लाक्षा विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर एवं विज्ञान संचारक डॉ. रुचा जोशी तथा एयरोस्पेस इंजीनियर एवं प्लाक्षा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शशांक तमास्कर भी उपस्थित रहे।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने पौने 37 करोड़ रूपए के जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का किया भूमिपूजन

पेयजल व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा,यह कार्य-उद्योगमंत्री

रायपुर/ संवाददाता

वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के पौने 37 करोड़ रूपये की लागत वाले जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का भूमिपूजन किया, इस कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात निगम क्षेत्र की ऐसे बस्तियाँ जहाँ पानी की किल्लत थी, वह समस्या अब दूर होगी तथा समस्याजनित बस्तियों, पारों एवं मोहल्लों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ) से 36 करोड़ 73 लाख रूपये की लागत से जलप्रदाय योजना का विस्तार कार्य किया जाना हैं, इसके अंतर्गत 20 एमएलडी के जलउपचार संयंत्र के साथ-साथ इमलीडुग्गू में 12 लाख 60 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी, दादरखुर्द में 22 लाख 50 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी एवं रूमगरा में 10 लाख 80 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी यानी उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया जाएगा, वहीं 15.3 किलोमीटर पाईप लाईन भी बिछाई जाएगी। योजना के पूर्ण होने पर इमलीडुग्गू मोतीसागरपारा, भिलाईखुर्द, बरबसपुर, कर्रानाला, मानिकपुर, रूमगरा, ढेलवाडीह, खरमोरा, दादरखुर्द, बेलगिरी बस्ती में निवासरत नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ निचले स्तर पर स्थित बस्तियों जहाँ पर लो प्रेशर के फलस्वरूप पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी, उन समस्त स्थानों में निर्वाध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी तथा नगर निगम कोरबा क्षेत्र की लगभग 60 हजार जनसंख्या इस कार्य से लाभान्वित होंगे। आज इमलीडुग्गू गौमाता चौक में आयोजित भूमिपूजन कायक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण विकास कार्य का भूमिपूजन उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत के हाथों सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हम सबको जिला खनिज न्यास मद के रूप में एक बड़ी सौगात दी है, जिसके परिणाम स्वरूप जिलों में अरबों रूपये के विकास कार्य इस मद के अंतर्गत

हो रहे हैं, उन्होने कहा कि आज जिस महत्वपूर्ण पेयजल योजना विस्तार कार्य का शुभारंभ किया गया है, वह भी जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत हुआ है। उन्होने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की सोच है कि हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हों, हर घर में बिजली की सुविधा व शौचालय हों, हर घर तक पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हों, और इन्ही सब का परिणाम है कि आज इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश में दर्जनों जनकल्याणकारी व गरीब हितैषी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है, उनकी समस्याएं दूर हो रही हैं। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज इस महत्वपूर्ण कार्य का भूमिपूजन किया गया है, इस कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात निगम क्षेत्र की ऐसी बस्तियों जहाँ पानी की किल्लत थी तथा पानी की कम आपूर्ति होती थी, वहाँ पर पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो सकेगी तथा पानी की किल्लत दूर होगी। महापौर श्रीमती राजपूत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में देश व प्रदेश का चहुमुंखी विकास हो रहा है, वहीं कोरबा के विकास के लिये उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पेयजल योजना विस्तार का यह कार्य निगम की पेयजल व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा तथा आमनागरिकों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होने कहा कि विगत 12 साल में केन्द्र सरकार के द्वारा देश व प्रदेश का तेजी से विकास किया गया है, 12 साल में लाखों किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आयें हैं तथा 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना में निःशुल्क इलाज हो रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी केसाथ ही पार्षद अशोक चावलानी, नरेन्द्र देवांगन।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13-17 जुलाई तक चलेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें प्रश्नोत्तर, शासकीय कार्य और वित्तीय मामलों चर्चा होगी। पहले 4 दिनों तक प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों के साथ गैर-शासकीय कार्य भी लिए जाएंगे। सदन में स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, किसानों, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों में हुए विवादित फैसलों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। चूंकि सत्र की अवधि केवल 5 दिन रखी गई है, इसलिए विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है।

छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिजली बिल चुकाना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और उपभोक्ताओं को अगस्त महीने में मिलने वाले बिल में इसका असर दिखाई देगा। बिजली कंपनी ने आयोग के समक्ष बिजली दरों में 24 प्रतिशत वृद्धि और 6,304 करोड़ रुपये के घाटे का दावा किया था, लेकिन आयोग ने विस्तृत समीक्षा के बाद केवल 6.23 प्रतिशत बढ़ोतरी तथा 1,662 करोड़ रुपये के घाटे को ही स्वीकार किया है। इससे उपभोक्ताओं को प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी से राहत मिली है। आयोग ने प्रदेश में प्रति यूनिट बिजली की औसत आपूर्ति लागत 7.13 रुपये निर्धारित की है। नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को भेज दी गई है। अब बिजली कंपनी घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग स्लैब के अनुसार नई दरों का विस्तृत चार्ट जारी करेगी। 1 जुलाई के बाद होने वाली बिजली खपत का बिल नई दरों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं को अगस्त महीने में करना होगा। बिजली दरों में हुई इस वृद्धि का असर प्रदेश के लाखों घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, हालांकि आयोग के फैसले से प्रस्तावित 24 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है।

फ्रुटी के पैकेट में मिली फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु बच्ची अस्पताल में भर्ती

रायपुर। जिले के मगरलोड क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। करेलीबड़ी गांव में एक मासूम बच्ची द्वारा खरीदी गई फ्रूटी के पैकेट में फंगस जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं, खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बच्ची ने गांव के एक जनरल स्टोर से फ्रूटी खरीदी थी। घर पहुंचकर जब वह जूस पी रही थी, तभी परिजनों की नजर पैकेट के अंदर पड़ी। पैकेट में कोई संदिग्ध वस्तु या फंगस जैसी सामग्री तैरती हुई दिखाई दी। इसे देखकर परिजन घबरा गए और तुरंत बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने संबंधित जनरल स्टोर से फ्रूटी के सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि संबंधित उत्पाद किस डीलर या थोक विक्रेता के माध्यम से दुकान तक पहुंचा था। इस घटना के बाद खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उनके रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं बाजार में नकली उत्पाद तो नहीं बेचे जा रहे हैं।

मनशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2.84 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2.842 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफएनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भाठागांव रिंग रोड स्थित वालफोर्ट गेट के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है।

समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया राज्यपाल ने

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायक है,मानव बुद्धि का विकल्प नहीं

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका आज डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर एवं आईसेक्ट इंडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित दो दिवसीय समर्थ भारत कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ तकनीक भी निरंतर विकसित हो रही है। ऐसे समय में तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो चिकित्सा, कृषि, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में मानव की सहायक बन सकती है, लेकिन यह मानव बुद्धि, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का स्थान नहीं ले सकती। तकनीक को जीवन में सहायक के रूप में अपनाया जाना चाहिए न कि उसे किसी खतरे के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एआई और अन्य नई तकनीकों का उपयोग नवाचार तथा समाज हित के कार्यों में करें। अपने संबोधन में उन्होंने इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। डिजिटल एडिक्शन न हो यह कोशिश करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि मानव सभ्यता का विकास सदैव नवाचार और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हुआ है। जिस प्रकार अग्नि की खोज ने मानव जीवन को नई दिशा दी, उसी प्रकार आधुनिक विज्ञान और तकनीक भविष्य के भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग समय की मांग है। स्टार्टअप और नवाचार केवल आर्थिक प्रगति के साधन नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम भी हैं। नवाचार के जरिए दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाया

जा सकता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं तथा समाज को नई संभावनाओं से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और इको-फ्रेंडली जीवनशैली को अपनाने पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को अपनाना आज की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक समृद्ध आदिवासी संस्कृति और अपार संभावनाओं वाला राज्य है। यहां के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और अवसरों से जोड़ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि, वन उत्पाद, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित प्रत्येक क्षेत्र में वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि भारत के गांवों तक तकनीक और नवाचार का लाभ पहुंचाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है इस तरह तकनीकी क्षेत्र में भी राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कंपनियों को जिस तरह के कोर्स की आवश्यकता है उसी के अनुरूप तकनीकी संस्थानों में कोर्स संचालित करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार युवाओं को हर तरह से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है जिससे युवा जाब मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार घोष ने एआई के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला।

छग में मानसून की दस्तक तय अगले 48 घंटे में बस्तर से एंट्री

- रायपुर समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री अब बेहद करीब पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों के चलते अगले 48 घंटों के भीतर मानसून बस्तर संभाग के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। लंबे इंतजार के बाद मानसून की आहट से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से मानसून की गति धीमी होने के कारण प्रदेश में गर्मी का असर फिर बढ़ गया है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। हालांकि बादलों की आवाजाही और कहीं-कहीं हल्की बारिश की वजह से कुछ इलाकों में राहत भी महसूस की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बालोद में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य पाकिस्तान से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक एक द्रोणिका (ट्रफलाइन) सक्रिय है। इसी सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में मौसम लगातार बदल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसमीय प्रणाली के कारण कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

घरेलू विवाद में बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या,आरोपी हिरासत में

रायपुर। जिले के डभरा थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के दौरान एक युवक ने अपनी ही मां की पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान भेड़िकोना गांव निवासी तिहारिन बाई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। पड़ोसियों के मुताबिक मारपीट के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन और आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिलने तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी।

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की ढुलमुल रवैये

सरकार की लापरवाही के चलते मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिली मान्यता-विनोद....

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की ढुलमुल रवैये और काम करने की ईच्छाशक्ति में कमी के चलते प्रदेश को मिलने वाली 5 नई मेडिकल कॉलेज को एनएमसी द्वारा मान्यता नहीं दिए जाने पर पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने इसे भाजपा सरकार की अक्षमता व लापरवाही का नतीजा कहा है। श्री चंद्राकर ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दंतेवाड़ा (गीदम), मनेंद्रगढ़, कुनकुरी (जशपुर), जांजगीर-चांपा और कवर्धा में प्रस्तावित 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से साफ इनकार करना सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक है। श्री

चंद्राकर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय उनके विधायकी कार्यकाल में महासमुंद के मेडिकल कॉलेज को शुरू कराया था। साल दर साल एनएमसी के मापदंड अनुरूप शर्तों को पूरा कर रात-रात भर बैठकर अनुमति दिलाई जाती थी। एमबीबीएस सेशन की परमिशन के लिए एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बॉडी की कमी के कारण शिक्षा सत्र की अनुमति न रुके इसलिए श्री चंद्राकर ने स्वयं 25000 रुपए राशि खर्च कर बॉडी की व्यवस्था कराई थी। अपने विधायक निधि से उन्होंने 25 लाख रुपए तत्काल प्रदान कर फर्नीचर डिसेक्शन हॉल, लेक्चरर थियेटर, लाइब्रेरी सेटअप, लैब इक्विपमेंट आदि की व्यवस्था कराई, वहीं स्टाफ की कमी की वजह से शिक्षा सत्र की मान्यता पर समस्या न आये इसके लिए एक निजी होटल में डॉक्टरों की रुकने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफहो और मेहनत की जाए तो सब संभव है। भाजपा सरकार के पास न नीयत है, न मेहनत करने का जज्बा। सरकार की लापरवाही के कारण 250 सीटों का नुकसान हो गया। इन कॉलेजों से 250 नई एमबीबीएस सीटें मिलनी थीं।

रामकृष्ण हॉस्पिटल में हो सकेगा पत्रकारों का रियायती दर पर इलाज

- रायपुर प्रेस क्लब में स्वास्थ्य शिविर का 'आभार एवं समापन समारोह' संपन्न
- डॉ. संदीप दवे की बड़ी घोषणा : पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर अब 30 तक बढ़ा

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के तत्वावधान में रायपुर प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्यों, पत्रकार साथियों एवं उनके परिजनों के लिए आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आभार एवं समापन समारोह आज रविवार को रायपुर प्रेस क्लब, मोती बाग में गरिमामयी माहौल में संपन्न हुआ। रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल, रायपुर द्वारा आयोजित इस शिविर के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप दवे उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सतीश थोरानी ने की। इस दौरान रायपुर प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. संदीप दवे ने पत्रकारों की सामाजिक सहभागिता और उनके कठिन कार्य परिवेश की सराहना की। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों और उनके परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर की अवधि को अब 30 जून 2026 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। पूर्व में पत्रकारों को जारी किए गए कूपन के माध्यम से वे इस विस्तारित अवधि तक अपनी निशुल्क जाँचें करवा सकेंगे। डॉ. संदीप दवे ने पत्रकार जगत को एक और बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि शिविर समाप्त होने के बाद भी रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए विशेष रियायतें जारी रहेंगी। इसके तहत: नि:शुल्क ओपीडी की सुविधा मिलेगी। दवाइयों पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। हॉस्पिटल चार्ज (अस्पताल के अन्य शुल्कों) में 30 प्रतिशत की स्थायी छूट हमेशा लागू रहेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी और रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने इस मानवीय पहल के लिए रामकृष्णा केयर हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉ. संदीप दवे का आभार व्यक्त किया।

सुशासन तिहार 2026: बुजुर्गों को छड़ी, दिव्यांगों को बैटरी ट्राइसाइकिल प्रदान की

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग, जिला रायपुर द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई कर पात्र हितग्राहियों को आवश्यक सामग्री शिविर स्थल पर ही प्रदान की गई, वहीं जरूरतमंदों तक उनके गांव एवं निवास स्थान पर पहुंचकर भी सहायता उपलब्ध कराई गई। इससे हितग्राहियों को तत्काल लाभ मिला और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े।अभनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कठिया में आयोजित प्रथम निवारण शिविर में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर योगेश साहू एवं गणेश राम को बैटरी संचालित ट्राइसाइकिल, दिलेश्वर साहू एवं पूर्णराम साहू को ट्राइसाइकिल तथा दामिनी और लोकेश निराला को व्हीलचेयर प्रदान की गई।शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को भी छड़ियां वितरित कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई गई। हितग्राहियों ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से उन्हें समय पर सहायता

शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश हमारी प्राथमिकता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

- भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का समन्वय कर रही है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री साय
- स्कूली शिक्षा में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का संत समाज ने किया स्वागत

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत सुरेंद्र दास जी महाराज, शदाणी दरबार से श्री उदय लाल जी तथा कबीर आश्रम सोनपैरी के श्री देवकर साहब जी ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर संत-महात्माओं ने छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं नैतिक शिक्षा से जुड़े पारंपरिक श्लोकों और मंत्रों को पुन: शामिल किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया। संतों ने कहा कि पूर्व में विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर जैसे मंत्रों एवं भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराया जाता था, जिससे बच्चों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होता था। समय के साथ ये परंपराएं शैक्षणिक वातावरण से धीरे-धीरे विलुप्त होती गईं, किंतु अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुन: स्थापित करने की पहल अत्यंत स्वागतयोग्य है। संत समाज ने कहा कि विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र तथा अन्य प्रेरणादायी वैदिक एवं सांस्कृतिक प्रार्थनाओं का समावेश बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़ सकेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों के विकास का आधार भी है। हमारी सरकार बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों में शांतिपाठ, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र एवं अन्य प्रेरणादायी प्रार्थनाओं के समावेश से विद्यार्थियों में अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा। यह पहल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए एक संस्कारित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज

मुख्य सचिव विकासशील ने ली उच्च स्तरीय बैठक,स्वस्थ आयु के लिए योग थीम निर्धारित

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में आगामी 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। आयोजन को व्यापक और सफल बनाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संभावित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम सरगुजा जिले में आयोजित होगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इसके लिए सभी आवश्यक और पुख्ता तैयारियां समय से

पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने निर्देश दिए कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य के सभी जिलों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर अनिवार्य रूप से योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आयुष विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आपस में बेहतर समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है। जिला स्तर पर अधिक से अधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि 21 जून को ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट की पुन: परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि योग दिवस के आयोजनों के कारण नीट परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा या तकलीफ न हो।आयुष विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा इस बार व्यापक जनभागीदारी के निर्देश हैं। 14 जून 2026 से सुबह 6.15 बजे से 7.35 बजे तक ऑनलाइन योग अभ्यास सत्र के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आम नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-315-7008 जारी किया गया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर आसानी से पंजीयन कराया जा सकता है।

गोदावरी इस्पात प्रबंधन के खिलाफ भानुप्रतापपुर में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, अवैध पेड़ कटाई, प्रदूषण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

स्थानीय लोकाधिकार समिति ने कलेक्टर को सौंपा अल्टीमेटम: 15 दिनों में जांच और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन और चक्काजाम की चेतावनी

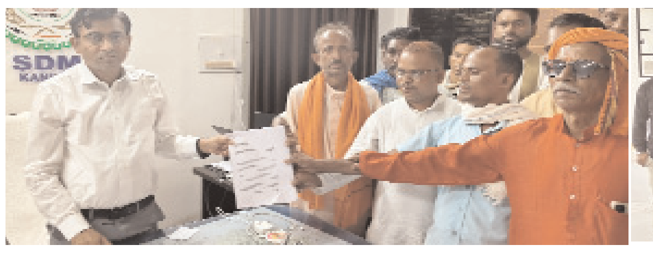

भानुप्रतापपुर। जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में गोदावरी इस्पात आरीडोंगरी कच्चे प्रबंधन की गतिविधियों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 'स्थानीय लोकाधिकार समिति' के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को दो अलग-अलग विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर कंपनी पर पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने, व्यापक स्तर पर अवैध वन कटाई करने, सीएसआर फंड में हेराफेरी करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित रखने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर इन सभी मामलों पर निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन और 'चक्काजाम' करने के लिए विवश होगी।

वृक्ष गणना में भारी विसंगतियां: 'खसरों की अवैध क्लबिंग' कर छुपाया गया वन घनत्व

कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई गई पहली शिकायत आरीडोंगरी माइंस क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत परेकोडो तहसील दुर्गूकोंदल में वन एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई वृक्ष गणना रिपोर्ट पर आधारित है, लोकाधिकार समिति के सदस्य हरेश चक्रधारी के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि लगभग 60.84 हेक्टेयर भूमि पर कंपनी को वेस्ट डंपिंग (कचरा फेंकने) की अनुमति देने के उद्देश्य से की गई वृक्ष गणना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और फर्जी है। ग्रामीणों के अनुसार, प्रशासन के संयुक्त दल ने खसरा क्रमांक 188/1, 247/1 एवं 100 को एक साथ जोड़कर क्लबिंग करके वृक्ष गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि नियमतः प्रत्येक खसरे का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्वरूप और वनस्पति घनत्व अलग-अलग है। ग्रामीणों का आरोप है कि संयुक्त गणना के पीछे असली मकसद उच्च वन घनत्व वाले क्षेत्रों को कम घनत्व वाला दर्शाना है ताकि वहां आसानी से माइनिंग कचरा डंप करने की अनुमति मिल सके। यह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ' मामले में पारित ऐतिहासिक दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है।

आंकड़ों का खेल: 2,000 से अधिक जीवित पेड़ों की गिनती गायब

जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि संयुक्त दल की रिपोर्ट में केवल 11,984 वृक्षों की उपस्थिति दर्शाई गई है। लोकाधिकार समिति का दावा है कि इस सर्वे में भारी लापरवाही बरतते हुए सैकड़ों घने पेड़ों को गणना से जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यदि इस संवेदनशील क्षेत्र की किसी निष्पक्ष और स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति से दोबारा गणना कराई जाए, तो वर्तमान रिपोर्ट से कम से कम 2,000 से अधिक अतिरिक्त वृक्ष मिलेंगे। इतनी भारी संख्या में पेड़ों को रिकॉर्ड से गायब करना कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत को उजागर करता है।

पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संकट

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि भले ही उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में 'पहाड़ चट्टान' मद में दर्ज है, परंतु वास्तविक धरातल पर वहां समृद्ध वनस्पति मौजूद है। यदि इस क्षेत्र में माइनिंग का वेस्ट डंप किया जाता है, तो इसके नीचे स्थित कृषि भूमि, जल स्रोत और स्थानीय जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। मिट्टी के कटाव (मृदा अपरदन) और भू-स्खलन का खतरा भी अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिससे अंततः स्थानीय आदिवासियों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

खुले में डस्ट निपटान से नदियां हो रही हैं जहरीली

लोकाधिकार समिति द्वारा सौंपे गए दूसरे मांग पत्र में गोदावरी इस्पात प्रबंधन द्वारा फैलाए जा रहे भयंकर वायु और जल प्रदूषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आरीडोंगरी खदान से परिवहन के दौरान और माइंस से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल (डस्ट) को खुले आसमान के नीचे डंप किया जा रहा है। इसके कारण उड़ने वाली धूल और बारिश के दिनों में बहकर जाने वाला कचरा स्थानीय नदियों के पानी को अत्यधिक दूषित कर रहा है, जिससे जन-स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही खनन विस्तार की आड़ में वन कानूनों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर जंगलों की अवैध कटाई की जा रही है।

लोकाधिकार समिति द्वारा प्रशासन के समक्ष रखी गईं मुख्य मांगें

त्रुटिपूर्ण वृक्ष गणना निरस्त हो: ग्राम पंचायत परेकोडो के तीनों खसरों की संयुक्त गणना रिपोर्ट तत्काल रद्द कर पृथक-पृथक वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए।

वेस्ट डंपिंग पर तत्काल रोक: जब तक निष्पक्ष सर्वेक्षण न हो, तब तक राजस्व भूमि पर कंपनी को किसी भी प्रकार के माइनिंग वेस्ट डालने की अनुमति न दी जाए।

स्थानीय युवाओं को अनिवार्य रोजगार: खदान प्रभावित क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत से गोदावरी इस्पात द्वारा कम से कम 150 स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अनिवार्य नौकरी दी जाए।

सीएसआर एवं डीएमएफ फंड की जांच व ऑडिट: अब तक कागजों में दिखाए गए सीएसआर और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के कार्यों का भौतिक व आकस्मिक ऑडिट हो और घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई हो।

प्रभावित पंचायतों की सूची सार्वजनिक हो: खदान के प्रभाव क्षेत्र यानी 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नामों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक की जाए।

प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम

शिकायत पत्र सौंपने के दौरान ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे लोकाधिकार समिति के पदाधिकारियों हरेश चक्रधारी, चंद्रमौली मिश्रा, रमल कोर्राम, संजू नेताम, जुगल कोरेटी, दिनेश कोरेटी, सुमन ध्रुव आदि ने कड़े शब्दों में कहा कि बस्तर एवं कांकेर क्षेत्र की जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपियां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानुप्रतापपुर, खनि अधिकारी कांकेर, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर को भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन आगामी 15 दिनों के भीतर इस विषय पर कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शरण में जाने के साथ-साथ क्षेत्र में उग्र जन-आंदोलन शुरू कर देंगे।

सड़कों और पुलों के निर्माण की धीमी गति पर बिफरे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पिछले सप्ताह चार दिनों के बस्तर प्रवास के दौरान अपने चारों विभागों के कार्यों का निरीक्षण कर गहन समीक्षा की थी। उन्होंने निरीक्षण और बैठकों के दौरान सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने काम में लापरवाही, देरी और अनुबंध के अनुसार अपेक्षित तेजी नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने चार पुलों के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स गुप्ता कन्सट्रक्शन कंपनी का पंजीयन दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। कंपनी द्वारा भवरडींग नदी पर अदनार-तोतर मार्ग, कोंडागांव के घोटिया-मुंडा-चांदाबेड़ा मार्ग और बड़े राजपुर विकासखंड के पलना-मरीगांव-कुंडई मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। कंपनी कबीरधाम जिले के बांटीपथरा से कुई (दमगढ़) मार्ग में हॉफ नदी पर भी उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कर रही है। चारों कार्यस्थलों पर कंपनी का काम अपेक्षित गति से काफी पीछे है। विभाग ने कांकेर के आमाबेड़ा-सेमर गांव सड़क पर नेरूल नदी तथा बोड़ागांव-खासगांव-तरादुल मार्ग में डुमरीकेल नाला पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के कार्य में लेट-लतीफी पर ठेकेदार निर्भय राम साहू का पंजीयन आगामी दो वर्षों के लिए निरस्त कर दिया है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद इन दोनों ठेकेदारों के काम की गति असंतोषजनक है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने नारायणपुर-सोनपुर-मरोदा मार्ग के चौड़ीकरण व सुधार कार्य की धीमी गति पर ठेकेदार पंकज हालदार को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। प्रमुख अभियंता ने सुकमा में पैकपारा-धनीकोड़ता मार्ग तथा केरलापाल-पटेलपारा-सिरसट्टी सड़क के कार्य में भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर ठेकेदार आशीष भदौरिया को पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया है। विभाग ने कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बी.एम.एस. प्रोजेक्ट, कोंडागांव में हडेली-कुदूर मार्ग के ठेकेदार मेसर्स सुराना एंड कंपनी और जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के ठेकेदार मेसर्स एस.के. अरोरा को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यस्थलों पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं होने पर सुकमा के चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क के ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, ट्रांससॉफ्ट इन्फ्रा और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन, कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के ठेकेदार मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स राघव कन्सट्रक्शन तथा भेज्जी-चिंतागुफा सड़क का निर्माण कर रहे ठेकेदार के. मोहन रेड्डी एवं गोविन्द्र सिंह देशमुख को लोक निर्माण विभाग के सुकमा संभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सड़कों व पुलों के निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लेट-लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में बंद हुए सभी टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य, एक अक्टूबर तक जंगल सफारी पर रोक

रायपुर। मानसून के आगमन और वन्यजीवों के प्रजनन काल को देखते हुए, हर साल की तरह इस वर्ष भी देश के अधिकांश टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जंगल सफारी 15 जून से 1 अक्टूबर तक साढ़े 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है । पीसीसीएफएवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय ने बताया, हर साल मानसून के पहले टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को बंद कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रकृति और वन्यजीवों की सुरक्षा तथा उनके प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) और वन्यजीव अभयारण्यों को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मानसून के आगमन के साथ ही जंगलों में पर्यटन गतिविधियों पर यह अस्थायी रोक आगामी 1 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर 2 अक्टूबर से जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी। वन विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, इस रोक के पीछे दो मुख्य कारण हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जंगलों के भीतर स्थित कच्चे मार्ग और सफारी ट्रैक बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। लगातार बारिश से नदी-नालों में उफान और रास्तों में

कोंडागांव डोकरा हस्तशिल्प में महत्वपूर्ण योगदान है देवेंद्र का

कोंडागांव। भेलवांपदर पारा के सन् 1999 में मध्यप्रदेश के राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार विजेता व सन् 2003 में राज्य पुरस्कार विजेता तथा सन् 2006 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कालीदास सम्मान एवं सन् 2009 में राष्ट्रीय मेरिट सम्मान भारत सरकार द्वारा प्राप्त सिद्धहस्त डोकरा हस्तशिल्पि देवेंद्र मंडावी का महत्वपूर्ण योगदान है कोंडागांव डोकरा हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में। पेशे से वन विभाग कोंडागांव में लिपिक कार्यरत देवेंद्र शासकीय सेवक से पहले से ही सिद्धहस्त राज्य पुरस्कार विजेता है तथा इनका नाम नामचीन हस्तशिल्पियों में शुमार हैं। जनजाति समुदाय से संबंधित देवेंद्र की हस्तशिल्प साधना काफी लंबी है ; उतनी ही रोचक इनकी कला के क्षेत्र में संघर्ष यात्रा भी है। देवेंद्र बताते हैं कि राज्य पुरस्कार विजेता बनने के बाद से एक भी ऐसा अवसर नहीं चुका है, कि उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हेतू अपनी प्रविष्ठि ना सम्मिलित किया हो किंतु वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। इस बार उन्होंने साठ किलोग्राम की वजनी कलाकृति राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता हेतू प्रविष्ट किया है। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण प्रतियोगिता जो कि कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में आयोजित किया गया है में उनकी कलाकृति चयनित हो गई है; अब अंतिम चयन प्रतियोगिता जो कि नई दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में होगी वहां पर चयन सुनिश्चित होना है। अपनी महीनों की अथक परिश्रम तथा कल्पनाशीलता से देवेंद्र ने अदभुत हस्तशिल्प कारीगरी प्रस्तुत किया है। जो कि तथागत बुद्ध से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि इस बार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (हस्तशिल्प) से छत्तीसगढ़ के पंद्रह में से 06 हस्तशिल्पि कोंडागांव जिला से चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त किए हैं।

जैविक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल: मंत्री कश्यप

दंतेवाड़ा। किसानों और कृषि प्रेमियों को रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक और टिकाऊ खेती करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित की गई है। दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं।

यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां और किसानों की मेहनत जैविक कृषि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ी है। जैविक खेती अपनाकर किसान भूमि की उर्वरता बनाए रखने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार भी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे भूमि संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक चौतराम अटामी ने कहा कि जिले के किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाकर बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर खेती को अधिक उन्नत एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने किसानों से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन तथा जैविक उत्पादों के विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को दी। किसानों की समस्याओं का समाधान भी विशेषज्ञों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग तथा भूमगादी संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को कृषि आदान सामग्री एवं आम के पौधों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा रागी से तैयार केक का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने केक काटकर महिला समूहों के प्रयासों की सराहना की और मूल्य संवर्धन आधारित गतिविधियों को ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने संबंधी राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राज्य की प्रमुख नदियों के पुनरूद्धार एवं पुनर्जीवित करने गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवाहित हो रही नदियों के पुर्नजीवन हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। नदियों का संरक्षण से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में बैठक में जिलों के कलेक्टरों से नदियों के कैचमेंट एरिया में बनायी गई विविध जल संरक्षण एवं संचयन की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नदियों के पुनर्जीवित एवं पुनरूद्धार के कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से नदियों के कैचमेंट एरिया में ऐसे जनउपयोगी कार्यों को लिया जाए जो भविष्य में नदियों के आस-पास रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने नदियों के कैचमेंट एरिया में किए जाने वाले कार्यों से स्थानीय सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि जिले से उद्गम होने वाली नदियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखी जाए। जिससे नदियों के बारे में छात्रों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं का भ्रमण नदियों के उद्गम स्थल पर कराया जाए और नदियों की जानकारी के संबंध में छात्रों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कलेक्टर ने नदियों के उद्गम स्थलों पर मेला उत्सव जैसे आयोजनों को करने के लिए भी कहा। बैठक में कलेक्टर रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में स्थित नदियों की वास्तविक स्थिति और संचालित कार्ययोजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों को नदियों के संरक्षण, संवर्धन के लिए जिला स्तरीय समितियों के संबंध में जानकारी दी।

सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में अंतर, रेगड़गट्टा में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे ग्रामीण

कोंटा। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है, यह उनकी वास्तविक तस्वीर सामने लाता है। कोंटा विकासखंड के ग्राम पंचायत रेगड़गट्टा में ग्रामीणों ने योजनाओं के सही तरीके सेसंचालन और मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जताई है। कुल 130 घर और 750 की आबादी वाले इस पंचायत में ग्रामीणों का कहना है कि कई योजनाएं धरातल पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं। नियमों के विपरीत और निम्न गुणवत्ता वाले कार्यों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि योजनाओं का उद्देश्य गांव का विकास और लोगों को सुविधा पहुंचाना है, लेकिन सही क्रियान्वयन नहीं होने से योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अप्रैल से खराब हैंडपंप, 600 मीटर दूर से ला रहे पानी

ग्रामीणों के अनुसार रेगड़गट्टा में अप्रैल माह से हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी कई बार जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें करीब 600 मीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव में कुल तीन हैंडपंप खराब होने से पेयजल की समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या से सरपंच व सचिव को भी अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं होने के बाद अब उन्हें अपनी समस्या सामने लाने के लिए पत्रकारों का सहारा लेना पड़ रहा है।

तीन महीने से बिजली व्यवस्था ठप, ग्रामीणों में नाराजगी

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के सरपंचपारा और पटेलपारा में पिछले तीन महीने से बिजली व्यवस्था बंद है। इस संबंध में कई बार सरपंच माड़वी जोगा को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग भी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। वहीं पंचायत के कुम्हारपारा में बिजली संचालित हो रही है, लेकिन सरपंच पारा और पटेलपारा के ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों का आरोप, सचिव नहीं सुनते समस्याएं

ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत सचिव उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुनते हैं, जबकि गांव में कई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती-किसानी के लिए डबरी, तालाब जैसे जल संरक्षण कार्यों की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पंचायत सचिव के नियमित रूप से गांव में नहीं आने और ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने के कारण उनकी मांगें पूरा नहीं हो पा रही हैं।

नल जल योजना पर भी उठे सवाल

ग्रामीणों ने नल जल योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गांव में घर-घर नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाना ही नहीं है तो ऐसी योजनाओं का निर्माण केवल दिखावे के लिए क्यों किया जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खराब हैंडपंप, बिजली व्यवस्था और नल जल योजना जैसी मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गांव के लोगों तक पहुंच सके।

-अमानत राशि राजसात, तीन निर्माण कार्यों की निविदाएं निरस्त

दुर्ग निगम के दो ठेकेदार 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट

दुर्ग/ दुर्ग नगर निगम में निविदा शर्तों का पालन नहीं करने और कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले दो ठेकेदारों को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन तथा ठेकेदार शशांक सिंह बैंस को निगम की सभी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उनकी जमा अमानत राशि राजसात करते हुए संबंधित निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है।

विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार अधोसंरचना मद अंतर्गत साइंस कॉलेज के बाजू केनाल रोड निर्माण कार्य हेतु मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन द्वारा 10.99 प्रतिशत कम दर पर निविदा स्वीकृत कराई गई थी। निविदा स्वीकृति के बाद अंतर की राशि 4.37 लाख रुपये का एफडीआर जमा कर अनुबंध निष्पादित करने के लिए निगम द्वारा कई बार पत्राचार किया गया, किंतु पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद ठेकेदार द्वारा न तो एफडीआर जमा किया गया और न ही अनुबंध निष्पादित करने के लिए उपस्थिति दी गई। इसे निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए निगम ने 2.20 लाख रुपये की अमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी तथा फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी प्रकार ठेकेदार शशांक सिंह बैंस द्वारा वार्ड क्रमांक 22 रेलवे लाइन के पास दुर्गा टेंट हाउस तक रोड निर्माण कार्य तथा वार्ड क्रमांक 60 तालाब के किनारे मेन रोड से मंच तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 25.22 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत कम दर पर निविदा प्रस्तुत की गई थी। दोनों कार्यों में नियमानुसार अंतर की राशि का एफडीआर जमा करने हेतु विभाग द्वारा बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर एफडीआर प्रस्तुत नहीं किया गया। निविदा शर्तों के उल्लंघन के चलते वार्ड 22 के कार्य में जमा 17,800 रुपये तथा वार्ड 60 के कार्य में जमा 23,500 रुपये की अमानत राशि राजसात कर ली गई है। साथ ही दोनों निविदाओं को निरस्त करते हुए ठेकेदार शशांक सिंह बैंस को भी आगामी एक वर्ष तक नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा आमंत्रित सभी निविदाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुबंध की शर्तों की अवहेलना अथवा कार्यों में अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खाद-बीज संकट पर भूपेश बघेल ने साधा सरकार पर निशाना

अम्लेश्वर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औंधी, सांकरा एवं झीट स्थित सेवा सहकारी समितियों का दौरा कर किसानों को उपलब्ध कराई जा रही खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने किसान भाइयों, मातृशक्ति एवं समिति सदस्यों से आत्मीयतापूर्वक संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, चिंताओं और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। किसानों ने खेती-किसानी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। किसानों के चेहरे पर झलकता विश्वास और उम्मीद इस बात का संकेत था कि संवेदनशील नेतृत्व के सामने जनता अपनी बात खुलकर रख पाती है। बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों के सामने खाद एवं बीज की उपलब्धता को लेकर गंभीर स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि साय सरकार के कार्यकाल में किसान पर्याप्त खाद के बिना ही धान की बुवाई करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं शासन से किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने तथा खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता कराने की मांग की।

नैनो उर्वरकों से बढ़ी आय, सुधरी मिट्टी की सेहत

- **नैनो उर्वरक लंबे समय तक मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और गुणवत्ता को बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय है : कृषक त्रिभुवन**

दुर्ग। आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करना आज के समय में टिकाऊ खेती की ओर एक बड़ा कदम है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दुर्ग जिले के ग्राम महमरा के प्रगतिशील किसान त्रिभुवन ने पेश किया है, जो आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए एक नई मिसाल बन गए हैं। उन्होंने अपनी फसलों में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है। इस नवाचार के फलस्वरूप उन्होंने पारंपरिक रूप से होने वाली भारी-भरकम उर्वरक लागत में बड़ी कमी लाई है, साथ ही अपनी खेती को पहले से कहीं अधिक लाभकारी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। अपने अनुभवों को साझा करते हुए त्रिभुवन का बताते हैं कि नैनो उर्वरकों के उपयोग से उनकी फसलों की वृद्धि बहुत बेहतर और तेजी से हुई है। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक बोरा बंद उर्वरकों की तुलना में बेहद कम मात्रा में छिड़काव करने के बावजूद इसके परिणाम कहीं अधिक प्रभावी और संतोषजनक प्राप्त हुए हैं। इस तकनीक के कारण उनकी कृषि लागत में भारी बचत हुई है, जिससे सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती मिली है। कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाने की उनकी यह कला अब आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। त्रिभुवन का दृढ़ विश्वास है कि नैनो उर्वरक केवल वर्तमान समय में फसल का उत्पादन बढ़ाने का एक शॉर्टकट माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह लंबे समय तक मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उसकी गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी एक सबसे प्रभावी उपाय हैं। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से बंजर होती धरती को बचाने के लिए उनकी यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि भूमि को पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और उपजाऊ बनाए रखने की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है।

पीडीएस की कालाबाजारी : खाद्य विभाग के मौन रूट से बाजार और फिर मिलर्स तक पहुंच रहा चावल

शहर से लगी राइस मिलों में पहुंच रहा सरकारी चावल, मॉनिटरिंग औपचारिक

राजनांदगांव। खाद्य विभाग की मिलीभगत का ही नतीजा है कि पीडीएस में मिलने वाला चावल लंबे समय से खुले बाजार में बिक रहा है, कहीं राशन दुकान संचालक भी इसकी खरीदी कर रहे हैं। लेकिन विभाग इस पर आंख मूंदकर बैठा हुआ है।

यहीं कारण है कि गरीबों का चावल खुले बाजार से होकर सीधे राइस मिलरों तक आसानी से पहुंच रहा है और बिचौलिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। गरीबों के कोटे का चावल सीधे राइस मिलर्स के पास पहुंचने लगा है। शहर कोटे का गरीबों का चावल 8 से 10 किलोमीटर की दूरी वाले राइस मिलर्स को खपाया जा रहा है। पूरा चैनल बनाकर यह काम किया जाता है। लंबे समय से इसी तरह सरकारी कोटे के चावल की कालाबाजी हो रही है और खाद्य विभाग इसे मौन स्वीकृति प्रदान किया हुआ है। इस कारण किसी भी पीडीएस संचालक या मिलर्स पर अब तक बड़ी

कार्रवाई नहीं की गई है। शहर में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे पीडीएस संचालक है जो गरीबों का चावल खुद ही खरीद लेते हैं। यानी राशन कार्ड में इंट्री करने के बाद उन्हें 22 से 24 रुपए किलो के भाव से भुगतान कर देते हैं।

इस तरह से जांच करने में पीछे है विभागीय टीम

सरकारी राशन दुकान हितग्राहियों से ही कोटे का चावल खरीद रहे हैं। इंट्री करने के बाद मशीन से स्टॉक को कम हो जाता है, मशीन के अनुसार कोटे का चावल हितग्राहियों को आवंटित किया जा चुका है। लेकिन दुकान में स्टॉक मौजूद रहता है, क्योंकि उसे तो संचालक ने ही खरीद लिया है। इमानदारी से यदि निरीक्षण किया जाए तो मशीन और दुकान के स्टॉक के मिलान से ही ये बड़ी गड़बड़ी पकड़ी जा सकती है।

चावल खरीदने एजेंट भी वार्डों में घूमते हैं

गरीबों का चावल पहले चरण में तीन लोगों के पास बिकता है, आखिर में पूरी खेप राइस मिलर्स के पास ही पहुंचती है। इसमें सरकारी राशन दुकान संचालक के अलावा कई किराना व्यापारी है जो सरकारी चावल खरीदते हैं। इसके अलावा शहर में कई ऐसे लोग हैं, जो एजेंट के रूप में वार्डों में जाकर हितग्राहियों से चावल लेते हैं। इसमें हितग्राहियों को जिसके पास प्रति रेट ज्यादा मिलता है वे उसी के पास चावल बेचते हैं।

किसानों को आवश्यकता के मुताबिक खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए : संभाग आयुक्त राठौर

संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने दिए निर्देश

दुर्ग। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने संभागीय कार्यालय में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और कामकाज की समीक्षा की उन्होंने कहा कि संभाग के सभी जिलों में किसानों को खरीफबीज और खाद की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संभाग में खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। संयुक्त संचालक कृषि ने अवगत कराया कि दुर्ग संभाग में 79 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 70 प्रतिशत खाद का भण्डारण किया गया है। अब तक 49 प्रतिशत खाद का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि संभाग के सभी जिलों में खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का वितरण शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। फसलों की आवश्यकताओं के आधार पर यूरिया की आवश्यकता तीन किस्तों में होती है। इसलिए दीर्घ श्रेणी के कृषकों को यूरिया दो किस्तों में उर्वरकों का

वितरण किया जा रहा है तथा लघु श्रेणी के कृषकों को यूरिया का वितरण रकबे के आधार पर एकमुश्त किया जा रहा है। संभाग में 81 प्रतिशत बीज का भण्डारण है। बीज निगम द्वारा किसानों के मांग के अनुरूप 50 प्रतिशत प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। अब तक किसी भी प्रकार की शिकायते नहीं आई हैं। धान की किस्म स्वर्णा और एमटीयू-1001 की मांग ज्यादा हो रही है। संभाग आयुक्त राठौर ने संभाग के जलाशयों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने मानसून को ध्यान में रखते हुए जलाशयों के पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि आज से स्कूल खुलने के साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हो। बच्चों को मध्यान्ह भोजन हेतु शहरों की भांति गांवों में भी अक्षय पात्र की सेवाएं दी जा सकती है। संभाग आयुक्त ने जल जीवन मिशन अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत गांवों में पेय जल उपलब्धता पर जोर देते हुए अधिकारियों को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत ही कार्य संपादित कराने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी प्रकार सुशासन तिहार के अंतर्गत अधीनस्त कार्यालयों को प्राप्त आवेदनों का भी गुणवत्ता पूर्वक निराकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त (राजस्व) पदुमलाल यादव और उपायुक्त (विकास) संतोष ठाकुर एवं समस्त विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

वाद-मुक्त ग्रामीण भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जिले के पांच गांवों में सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम प्रारंभ

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), नई दिल्ली द्वारा जारी मुकदमे-मुक्त ग्रामीण भारत की दिशा में सामुदायिक मध्यस्थता मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा जिले के पांच ग्रामों घुघसीडीह, ननकट्ठी, अरसनारा, निकुम एवं कुथरेल का चयन किया गया है। इस अभिनव पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले छोटे-छोटे सामाजिक, पारिवारिक, पड़ोसी, भूमि एवं अन्य सामुदायिक विवादों का न्यायालय पहुंचने से पूर्व ही आपसी संवाद, सहमति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण सुनिश्चित करना है। सामुदायिक मध्यस्थता की इस व्यवस्था से न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी, बल्कि गांवों में सामाजिक समरसता, भाईचारा एवं आपसी विश्वास को भी मजबूती प्राप्त होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा चिन्हांकित इन ग्रामों में सामुदायिक

मध्यस्थता तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएं एवं संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों, पैरामलीगल वालंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण नागरिकों को मध्यस्थता की प्रक्रिया एवं उसके लाभों से अवगत कराया जाएगा। सामुदायिक मध्यस्थता एक ऐसी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जिसमें पक्षकारों की स्वैच्छिक सहभागिता एवं आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है। यह प्रक्रिया सरल, त्वरित, कम खर्चीली तथा संबंधों को बनाए रखने वाली व्यवस्था के रूप में ग्रामीण समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे विवादों के समाधान हेतु संवाद एवं मध्यस्थता की संस्कृति को अपनाएं तथा ग्राम स्तर पर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं। यह पहल वाद-मुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण समाज में स्थायी शांति एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देगी।

पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन

भिलाई नगर। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा फुटकर विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सभी पात्र हितग्राहियों को नगर निगम कार्यालय में आमंत्रित कर योजना का लाभ दिलाने हेतु उनके ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में भरवाए गए। शिविर में बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स उपस्थित हुए तथा योजना के प्रति उत्साह दिखाया। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय जी के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में निगम की टीम द्वारा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस संबंध में नोडल अधिकारी अनिल सिंह द्वारा सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पत्र प्रेषित कर पात्र

हितग्राहियों को योजना का लाभ शीघ्र एवं अधिकतम संख्या में प्रदान करने हेतु आवश्यक सहयोग एवं प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा मुनादी एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए निगम क्षेत्र में प्रतिदिन जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा आगामी दिनों में भी ऐसे शिविरों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय भव्य 'योग संगम' का आयोजन

कलेक्टर ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

दुर्ग। 21 जून 2026 को 'योग संगम' एवं 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' थीम पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम मालवीय नगर चौक स्थित 'खालसा पब्लिक स्कूल' में सुबह 07.00 बजे से 07.45 बजे के मध्य आयोजित होगा। कलेक्टर सिंह ने कार्यक्रम की सफलता और व्यवस्थाओं के सुचारू प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिसके अनुसार जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग दुबे को संपूर्ण कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरवंश सिंह मिरी को कानून व्यवस्था, संपूर्ण तैयारी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है, वहीं संयुक्त कलेक्टर एवं प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में वे मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण कार्ड वितरण का कार्य भी संभालेंगे।

शहरी व्यवस्थाओं की कमान आयुक्त (नगर पालिक निगम) सुमित अग्रवाल को दी गई है, जिन्हें स्टेडियम में मैदान की सफाई, गद्दे, टेंट, दरी की व्यवस्था, भौतिक ढांचा, वीडियो व फोटोग्राफी, माइक तथा शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द मिश्रा को मंचीय संचालन हेतु उद्घोषिका (एनाउंसर) की व्यवस्था करने, योग प्रशिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा सभी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं, स्काउट गाइड और एनएसएस के छात्रों की भागीदारी तय करने का जिम्मा मिला है। कार्यपालन अभियंता (लोक निर्माण विभाग) आशीष भट्टाचार्य को आमंत्रण पत्र कार्ड प्रिंटिंग, मंच निर्माण और मंचीय बैनर व्यवस्था का प्रभार दिया गया है। चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिए सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशीषन मिंज को चिकित्सकीय टीम एवं एम्बुलेंस तैनात रखने की जिम्मेदारी दी गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आर. के. जामुलकर को आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल आश्रमों से जुड़े लोगों को कार्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप जांगड़े को सभी महाविद्यालयों में योग कार्यक्रम आयोजित कराने तथा छात्र-छात्राओं को जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित करने को कहा गया है।

भिलाई 03 के 'मंगल भवन' में 18 जून से लगेगा तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर

केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ

दुर्ग। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई-03 में तीन दिवसीय वृहद पंजीकरण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-03 महेश राजपूत से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विशेष शिविर आगामी 18 जून 2026 से 20 जून 2026 तक स्थानीय 'मंगल भवन, भिलाई 03' में आयोजित किया जाएगा, जिसका समय पूर्वान्ह 10.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस तीन दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाना है। शिविर के दौरान विभिन्न प्रमुख योजनाओं के लिए मौके पर ही पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम कौशल विकास योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं को शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो सकें। क्षेत्र के नागरिक और जरूरतमंद लोगों से तय समय पर 'मंगल भवन' पहुंचकर इस वृहद शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995